सुबह सवेरे
A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 06 मई, 2026
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 243, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

04 - रणनीति बनाम अहंकार, और कमजोर होती जड़ें

05 - ऋतु सौन्दर्य से परिपूर्ण जीवन की मौलिक परिभाषा

06 - सचिन शर्मा के रूप में धार को मिला नया कप्तान, पहले ही दिन...

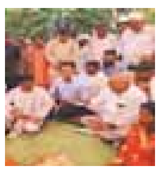
07 - संकट की घड़ी मध्यप्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के...

प्रसंगवश

प.बंगाल के चुनाव नतीजों का विपक्षी राजनीति पर क्या होगा असर?

चंदन कुमार जजवाड़े

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए बड़ा झटका हैं। जो पार्टी पिछले चुनावों में 215 सीटों पर जीतकर आई थी, वह इस बार सौ सीटें भी नहीं जीत पाई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि राज्य में उस पार्टी यानी बीजेपी को जीत मिली है, जिसका ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मुखर विरोध करती रही है।

ममता बनर्जी केंद्र में सत्ता पर काबिज़ बीजेपी के विरोधियों के बीच इतना बड़ा चेहरा थीं कि उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी खड़े दिखे और बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी। लेकिन कई विपक्षी नेताओं के समर्थन के बाद भी ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में नाकाम रही हैं। यह न केवल एक अहम विपक्षी पार्टी के लिए झटका है, बल्कि इसका असर केंद्र के स्तर पर विपक्षी दलों के प्रभाव पर भी पड़ सकता है।

साल 2024 के लोकसभा चुनावों में केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के ख़िलाफ़ बने 'इंडिया ब्लॉक' के बड़े चेहरे के तौर पर भी ममता बनर्जी को देखा जा रहा था, उन्होंने ही लालू प्रसाद यादव और उस समय विपक्षी गुट में रहे नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में करने की सलाह दी थी। यह ऐसी सलाह थी, जो मानी भी गई और इंडिया ब्लॉक की पहली बैठक पटना में हुई थी।

तृणमूल कांग्रेस केंद्र में तीसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। साल 2024 में विपक्षी दलों में उससे ज़्यादा सीटें केवल कांग्रेस (99) और एसपी (37) ने जीती थीं। टीएमसी को उन चुनावों में पश्चिम बंगाल की 42 में से 29 सीटों पर जीत मिली थी। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं, 'इस जीत के साथ ही बीजेपी अब पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर सेंधमारी की कोशिश करेगी। ममता बनर्जी एक बड़ी नेता हैं और उनकी पार्टी की हार विपक्ष को कमज़ोर करेगी। इससे बीजेपी ताक़तवर हुई है। विपक्षी दलों में एकता नहीं है यह स्पष्ट तौर पर दिखा। एसआईआर को विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी का सिरदर्द समझ लिया। ये सारे दल वैचारिक तौर पर अलग-अलग हैं, जबकि बीजेपी जो दक्षिणपंथी राजनीति करती है, उसका अब कोई विकल्प नहीं बचा है।'

विपक्षी दलों के लिहाज से बात करें तो इन चुनावों में केवल कांग्रेस थोड़े फ़ायदे में रही है।

केरल में कांग्रेस के गठबंधन यूडीएफ़ ने सत्ता में वापसी कर ली है, हालांकि असम में उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा है। जबकि तमिलनाडु में बीजेपी के विरोध में खड़े डीएमके नेता एमके स्टालिन की हार हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी कहती हैं, 'कुल मिलाकर विपक्ष कमज़ोर हुआ है। विपक्ष के सारे बड़े नेता हार गए हैं। इसका एक असर यह होगा कि विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का ज़्यादा विरोध किया और दबाव बनाने की कोशिश की तो उनकी फ़ाइलें खोली जाएंगी। इनमें ममता बनर्जी और एमके स्टालिन दोनों ही शामिल हैं।'

बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों को शरण देने और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। तमिलनाडु में भी बीजेपी और डीएमके के बीच कभी हिन्दी तो कभी सनातन के नाम पर विवाद होता रहा है।

बीते कुछ साल में कई राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद विपक्षी दल केंद्र के स्तर पर कमज़ोर हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जीत ने बीजेपी के लिए नया दरवाज़ा खोल दिया है। अब बीजेपी उन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ सकती है, जहाँ उसे कमज़ोर माना जाता है।

एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल स्टडीज (पटना) के पूर्व निदेशक और राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकर कहते हैं, 'बीजेपी को बिना विपक्ष की राजनीति चाहिए। इस हार के बाद विपक्ष को ख़ुद पर फिर से विचार करना होगा। संसदीय राजनीति में अवसरवाद इतना हावी है कि सब अपने बारे में सोचते हैं। लगता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा। अब राजनीति बीजेपी बनाम छोटे-छोटे दलों की बची हुई है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद है।'

रशीद किदवई कहते हैं कि विपक्ष की एकता या रणनीति केवल काग़ज़ों पर बनती है। अगर कांग्रेस ने तमिलनाडु में विजय की पार्टी से समझौता कर लिया होता तो उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता, लेकिन पी चिदंबरम ने मना किया तो कांग्रेस साथ नहीं गई।'

23 जून, 2023 को पटना में साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुक़ाबला करने के लिए विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इस बैठक के कुछ ही महीने बाद ही नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी गुट का साथ छोड़ दिया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। यह विपक्षी गठबंधन के लिए पहला बड़ा झटका था।

डीएम दिवाकर कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की हार से विपक्ष का मनोबल टूटेगा। लेकिन विपक्ष अगर सकारात्मक हो जाए और बिहार में हार के बाद जिस तरह निष्क्रिय होकर बैठ गया, वैसा न करे तो उसके लिए बेहतर होगा। ममता बनर्जी के मामले में एंटी इंकम्बेंसी थी और बीजेपी जिस तरह से आक्रामक थी तो यह दिख रहा है कि उन्हें ताक़त के ज़रिए हराया गया है। इसमें एसआईआर कराना भी शामिल है। चुनाव आयोग का काम है कि वह चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ाए, लेकिन वह घटाने में लगा है. यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।'

विपक्ष के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार रैली कर रहे थे, तब इसमें ममता बनर्जी शामिल नहीं हुईं, और जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा था तब भी विपक्षी दलों ने पूरी ताक़त से इस मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया। नीरजा चौधरी कहती हैं कि ममता बनर्जी की इस हार के बाद विपक्ष के सामने रास्ता यही है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करे और कांग्रेस भी बड़ा दिल दिखाए। अगर ऐसा हो जाता है तो विपक्ष आगे बढ़ पाएगा। यह समय न केवल विपक्षी दलों के लिए अहम है, बल्कि बीजेपी के लिए भी अहम है कि अब विपक्ष की क्या रणनीति रहती है। वहीं, रशीद किदवई का मानना है, 'बीजेपी अगर हारती है तो उसी दिन से अगली तैयारी में लग जाती है, जबकि विपक्ष हार के बाद उदासीन होकर बैठ जाता है, जैसे बिहार में हार के बाद विपक्ष उदासीन होकर बैठ गया, उन्हें वहां जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं दिखता।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

इस्तीफा नहीं दूंगी, हम हारे नहीं, हराया गया

● ममता बनर्जी बोलीं-मैं आजाद पंछी, शेर की तरह लड़ूंगी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता ने कहा- हम जनादेश नहीं, साजिश से हारे हैं। इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग असली विलेन है। उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटीं। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूं। कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, सड़कों पर रहूंगी। ममता ने आरोप लगाया- भाजपा ने काउंटिंग सेंटरों पर कब्जा कर लिया था। मेरे साथ बदसलूकी की। उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया। ममता ने कहा- पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेता मेरे साथ हैं। हम फिर से उभरेंगे और शेर की तरह लड़ेंगे।

टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले

ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता से जगह जंगल महल तक एक जैसा माहौल है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जा रहा है। बीजेपी जिस तरह अत्याचार कर रही है, गुंडों को सामने रखकर तांडव मचा रखा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके साथ काउंटिंग सेंटर पर धक्का मुक्की की गई। उन्होंने कहा कि जब एक महिला कैंडिडेट के साथ ऐसा हो सकता है तो अन्य टीएमसी उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ होगा।

अमित शाह चुनेंगे बंगाल का सीएम

● पार्टी ने दी जिम्मेदारी, बनाए गए पर्यवेक्षक

जेपी नड्डा को मिली असम की जिम्मेदारी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल और असम में नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। असम के लिए जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर्यवेक्षक

होंगे। अमित शाह अगले 2-3 तीनों में कोलकाता जाएंगे और विधायकों से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। पहले शपथ समारोह रवींद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन यानी 7 मई पर होने की चर्चा सामने आई थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी को 206 सीटें हासिल हुई है, जबकि टीएमसी को 82 सीटें मिली हैं। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक की भूमिका में रहेंगे।

बंगाल के सीएम को लेकर सस्पेंस

पश्चिम बंगाल में सीएम पद की दौड़ में सुवेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं। ममता बनर्जी 15 साल तक राज्य की मुख्यमंत्री रहीं। ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी भूमिपुत्र सुवेंदु अधिकारी पर दांव खेलेगी या फिर किसी महिला को आगे करेगी। महिला सीएम होने की चर्चाओं ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक राजनीति को गरमा दिया है। सुवेंदु अधिकारी के अलावा कुछ और नाम भी चर्चा में हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का नाम शामिल है। महिला सीएम के लिए रूपा गांगुली और अग्निमित्रा पॉल का नाम चर्चा में है। सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भबानीपुर से जीत हासिल की है। बंगाल में इतिहास में अभी तक कुल आठ मुख्यमंत्री हुए हैं इनमें ममता बनर्जी इकलौती महिला सीएम हैं। ऐसे में चर्चा है कि महिलाओं के मजबूत नेटवर्कऔर वोटबैंक को देखते हुए क्या बीजेपी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर सुवेंदु ही सीएम बनेंगे। पिछली बार ममता बनर्जी ने पांच मई को शपथ ली थी। वह कुल 15 साल राज्य की सीएम रहीं।

मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए बड़े फैसले

राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड का होगा गठन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण के लिए विभिन्न विभागों की 38 हजार 555 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के व्यापारियों के कल्याण के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का

- **38 हजार करोड से अधिक की वित्तीय मंजूरी**
- **दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442.04 करोड़ रूपये की स्वीकृति**
- **सड़क निर्माण और आवास अनुरक्षण के लिए 32 हजार 405 करोड़ रूपये की स्वीकृति**

ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है। यह निर्णय प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

बैठक के प्रमुख निर्णयों में 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए सड़क निर्माण, ग्रामीण मार्गों के उन्नयन और शासकीय आवासों के रखरखाव के लिए सर्वाधिक 32 हजार 405 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी गई, इसमें आगामी 5 वर्षों में 2,442.04 करोड़ रुपये व्यय कर दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और मिशन वात्सल्य के सुचारू संचालन के लिए 2,412 करोड़ रुपये तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1,295 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रि-परिषद ने राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और सरकार के साथ सीधे संवाद का सशक्त माध्यम बनेगा। यह पहल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। मंत्रि-परिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क निर्माण और आवास अनुरक्षण के लिए 32,405 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।स्वीकृति अनुसार सड़क एवं सेतु के संधारण से संबंधित योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 6 हजार 150 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया गया है। इसी तरह 'एफ' टाईप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों के अनुरक्षण के लिए 1 हजार 345 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 2442.04 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की आगामी 5 वर्षों 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता के लिए 2442 करोड़ 04 लाख रूपये की स्वीकृति दी। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक नियम/दिशा-निर्देश जारी करने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अधिकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दलहन फसलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में से दलहन फसल को पृथक कर दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ किया गया। भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में नए मिशन दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है।

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

कोई नियम नहीं
सुन कर वह हॅंसा

कोई कानून नहीं
सुन कर वह हॅंसा

कोई न्याय नहीं
सुन कर वह हॅंसा

कोई नैतिकता नहीं
सुन कर वह हॅंसा

कोई मानवता नहीं
सुन कर वह हॅंसा

कोई शर्म नहीं
सुन कर वह हॅंसा

बहुत अत्याचार है
सुन कर वह हॅंसा

ये पाप है
सुन कर वह हॅंसा

ये धर्म नहीं
सुन कर वह हॅंसा

उसकी हॅंसी से जाना
तानाशाह कैसे हॅंसता है।

– चंद्रशेखर साकल्ले

घर-घर पहुंचे कार्यकर्ता, गुस्से को वोट में बदला

● बंगाल में परदे के पीछे से आरएसएस ने किया 'खेला'

नई दिल्ली (एजेंसी)। बंगाल चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई। इस जीत के साथ ही ममता के 15 साल के शासन का अंत हुआ। भाजपा की जीत के पीछे वैसे तो अनेक फैक्टर रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की करीब डेढ़ दशक लंबी तैयारी भी काम आई। साल 2011 में राज्य में करीब 530 शाखाएं थीं, जो 2500 से ज्यादा हो चुकी हैं। पिछले साल में 583 नई शाखाएं खुलीं। चुनाव से पहले संघ ने पर्दे के पीछे रहकर एक लाख से ज्यादा छोटी

बैठकों के जरिए परिवर्तन का नैरेटिव सेट कर दिया। 2021 की हिंसा के बाद संघ सुरक्षा कवच की भूमिका में आया। पीड़ितों के घर जाकर आर्थिक और कानूनी मदद दी। शीर्ष नेतृत्व से संवाद कराया। संदेश गया कि संगठन साथ है। संघ में संदेशखाली जैसे इलाकों में सीधे टकराव के बजाय भरोसे की रणनीति अपनाई। महिलाओं व पीड़ितों से संवाद के जरिए उन्हें बात उठाने को प्रेरित किया। बड़ी संख्या में लोग सामने आए। सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर काम किया। स्थानीय त्योहारों, विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए भाजपा को स्थानीय विकल्प के रूप में पेश किया।

डर तोड़ने का अभियान मुद्दों की लड़ाई

गांव-मोहल्ले तक पहुंच वोटर्स वर्कर्स में भरोसा बनाया कि निडर हो वोट दें। लोगों को बूथ तक लाने की तैयारी की। हर क्षेत्र - बूथ की जमीनी स्थिति भाजपा तक पहुंचाई। शिक्षक भर्ती घोटाला, आरजी कर व अन्य मामलों को परिवार और महिलाओं की सुरक्षा व भविष्य से जोड़ा। मुद्दे गांव और शहरी मध्यमवर्ग तक पहुंचाए। असंतोष को वोट में बदलने का माहौल बना।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 06 मई 2026

> जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
>
> चाणक्य नीति

यूपी व बिहार में आंधी बिजली ने ढाया 'कहर'

● 24 घंटे में 31 लोगों की मौत, दिल्ली में ओले गिरे

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में चक्रवात बनने से देश के बड़े हिस्से में मौसम बदल गया है। दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ट्रफ बनी हुई है, जिससे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का असर है। दिल्ली में मंगलवार दोपहर को ओले गिरे।

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में आंधी और तेज बारिश हुई। यूपी में आंधी-बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई। पीलीभीत में ईंट-भट्ठे की 100 फीट ऊंची चिमनी ढह गई। बिहार में 22 जिलों में आंधी-बारिश हुई। बिजली गिरने से 7 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। 2 महिलाएं झुलस गईं। आज 18 जिलों तेज बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में सोमवार को तापमान में 8 डिग्री की गिरावट आई। जयपुर समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 से कम रहा। हरियाणा में तेज आंधी से 15 हजार से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। हिमाचल प्रदेश के सोलन का तापमान सोमवार को 4.8 डिग्री रहा। यह मई महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 14 मई 2021 को 9.4 डिग्री तापमान रहा था। मध्य प्रदेश में मई महीने में तेज गर्मी की जगह बारिश और आंधी की स्थिति है। सोमवार को 15 जिलों बारिश और ओलावृष्टि का असर रहा। कई जगहों पर तेज आंधी भी चली।

हरियाणा में तूफान से 15 हजार से ज्यादा पेड़ उखड़े

मोदी सरकार का बड़ा किसान हितैषी फैसला

गन्ना किसानों को 2026-27 के लिए 365 रु. प्रति क्विंटल एफआरपी : शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में बड़ा, संवेदनशील और दूरदर्शी निर्णय लिया है। चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गन्ना किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उत्पादन का बेहतर प्रतिफल दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री चौहान ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मोदी सरकार किसानों की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया यह फैसला देश के करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। उन्होंने कहा कि 10.25 प्रतिशत की बेसिक रिकवरी दर पर 365 रु. प्रति क्विंटल एफआरपी स्वीकृत किया गया है। साथ ही, 10.25 प्रतिशत से अधिक रिकवरी पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए 3.56 रु. प्रति क्विंटल का प्रीमियम दिया जाएगा, जबकि 10.25 प्रतिशत से कम रिकवरी पर इसी दर से एफआरपी में कमी का प्रावधान है। शिवराज सिंह चौहान ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक अत्यंत मानवीय और किसान-पक्षीय निर्णय भी लिया है। जिन चीनी मिलों में रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम रहेगी, वहां भी किसानों के एफआरपी में कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसे किसानों को 338.30 रु. प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल मूल्य वृद्धि भर नहीं है, बल्कि किसानों को सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान देने का संकल्प भी है। चीनी सत्र 2026-27 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 182 रु. प्रति क्विंटल आंकी गई है, जबकि घोषित एफआरपी 365 रु. प्रति क्विंटल है, जो लागत से 100.5 प्रतिशत अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि नया एफआरपी वर्तमान चीनी सत्र 2025-26 की तुलना में 2.81 प्रतिशत अधिक है। श्री चौहान ने कहा कि देश का चीनी क्षेत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि आधारित क्षेत्र है, जो लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिजनों के जीवनयापन से जुड़ा है।

संक्षिप्त समाचार

सबरीमाला में वकीलों की याचिका, एससी नाराज

● कहा- पीआईएल अब पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) अब प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिसिटी इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई हैं। यह कमेंट नौ जजों की संविधान बेंच ने केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किया। कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के 2006 के पीआईएल के मकसद पर सवाल उठाया, जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि पीआईएल कानून

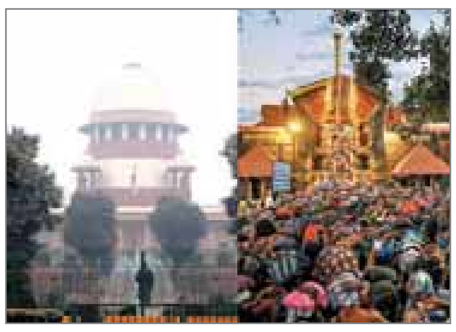

की प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है और एसोसिएशन को ऐसी पीआईएल फाइल करने के बजाय बार और अपने युवा सदस्यों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और अलग-अलग धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर 11वें दिन की सुनवाई चल रही है। सितंबर 2018 में 5 जजों की संविधान बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। तब कोर्ट ने कहा था कि सदियों पुरानी हिंदू धार्मिक प्रथा गैर-कानूनी और असंवैधानिक है।

9 शवों का अंतिम संस्कार देख छलक उठे सबके आंसू

● दिल्ली अग्निकांड में मरने वाले लोगों के परिवार पूछ रहे कई सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। विवेक विहार में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में जान गंवाने वाले सभी 9 लोगों का रविवार को जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम किया गया। इसके बाद निगम बोध घाट में शवों का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया गया। डेढ़ साल के बच्चे का अंतिम संस्कार दूसरी जगह किया गया। हादसे में अरविंद जैन समेत उनके घर के कुल 5 सदस्यों की मौत हो गई। उनका बेटा दीपक और बहू सोनाली मानेसर में अपने जुड़वा बेटों का जन्मदिन मनाने गए थे। परिवार के बाकी लोगों को भी रविवार को वहां जाना था, लेकिन इससे पहले ही यह हादसा

हो गया। **आंखों से नहीं रुक रहे आंसू-** अंतिम संस्कार के दौरान किसी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। विवेक विहार के सी ब्लॉक स्थित अग्रसेन धर्मशाला में दीपक और सोनाली ने शोक सभा का आयोजन किया था। वहीं, सूर्य नगर स्थित जैन स्थान में नितिन के परिवार की ओर से भी शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नितिन के छोटे बेटे प्रांशुख बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें किसी तरह संभाला परिवार में अब सिर्फ वही बाकी हैं।

28 साल पहले शिफ्ट हुए थे परिवार

दूसरी तरफ सोमवार को पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा था। कुछ पीड़ितों के रिश्तेदारों और जानकारों का आना-जाना लगा था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। बस खामोशी थी। कई लोग अपना बचा हुआ सामान इमारत से निकालते नजर आए। एक पड़ोसी ने बताया कि ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग में करीब 1998 में शिफ्ट हुए थे।

अमेरिकी जांच के घेरे में भारत, 8 को आमना-सामना

● नई दिल्ली के पास आरोपों का है जवाब, कर चुका है खंडन

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका ने भारत को जांच में घेरा है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) कार्यालय में इस पर सुनवाई होने वाली है। उसने भारत पर कुछ मैन्युक्चरिंग सेक्टरों में ओवर कैपिसिटी और प्रोडक्शन का आरोप लगाया है। भारतीय व्यापार अधिकारी और उद्योग प्रतिनिधि 8 मई को अमेरिकी दावों का खंडन करने के लिए अपनी बात रखेंगे। यह मामला दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में एक अहम मसला है। यह सुनवाई ऐसे समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षपीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर बातचीत हो रही है। इसने काफी असमंजस की स्थिति पैदा की है। अमेरिका ने मार्च में अमेरिकी व्यापार

अधिनियम के सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि भारत ने पेट्रोकेमिकल्स, स्टील और सोलर मॉड्यूल में काफी ज्यादा अतिरिक्त क्षमता (एक्सेस कैपेसिटी) बना ली है। साथ ही, कपड़ा, स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री और ऑटोमोटिव सामान जैसे क्षेत्रों का भी जिक्र किया गया। इन सेक्टरों में नई दिल्ली के पास ग्लोबल ट्रेड सरप्लस है। भारत ने इन दावों को खारिज कर दिया है। इस सुनवाई में प्लास्टिक, सूती कपड़ा, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो कंपोनेंट्स (पुर्जो) से जुड़े उद्योगों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। 2025 में अमेरिका के साथ अपने 42 अरब डॉलर के बाइलेट्रल ट्रेड सरप्लस (व्यापार अधिशेष) के मुद्दे पर नई दिल्ली ने कहा कि दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष एक मैक्रोइकोनॉमिक घटना है। यह कई स्थितियों के मेल का परिणाम होती है। इसमें कुछ नॉन-मार्केट इकोनॉमीज की भूमिका भी शामिल है।

भारत के खिलाफ शुरू की है एक और जांच

इसके अलावा, यूएसटीआर ने 12 मार्च को भारत और कुछ अन्य देशों के खिलाफ एक और जांच शुरू की है। यह जांच फोर्स्ड लेबर के मुद्दे पर ऐक्शन न करने के आरोप में शुरू की गई है। इस मामले में भी भारत ने अपना पक्ष रखा है। यह कहते हुए कि ऐसी जांच जरूरी कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करती है।

विश्व हास्य दिवस पर हास्यास्पद व्यंग्य कार्यक्रम आयोजित

इंदौर। शालीमार टाउनशिप लाइब्रेरी में विश्व हास्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की शाम टाउनशिप के सदस्यों के चुटीले व्यंग्य और गुदगुदाते शालीन हास्य से बेहद खुशनुमा और अविस्मरणीय बना दिया। यह दिन लोगों को खुश रहने की प्रेरणा देता है और हंसी का महत्व समझाता है। इस कार्यक्रम ने

इस तथ्य को रेखांकित किया कि सहज हास्य मन को आनंदित करता है और वास्तव में मन से अवसाद और तनाव को दूर कर शांति का अनुभव कराता है। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक रोचक प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को सहज एवं नैसर्गिक हास्य के अवसर प्रदान किए। कैलाश जैन ने शैल चतुर्वेदी के चुटीले व्यंग्य प्रस्तुत किए। मृणालिनी घुले ने अपने आसपास घटने वाली घटनाओं पर आधारित हास्य कविताएँ और क्षणिकाएँ सुनाई। विजय रांगणेकर ने समाचार पत्रों में भविष्यफल पर आधारित स्वरचित व्यंग्य 'शत्रु की तलाश में' और 'हमने भी एक ब्रीफकेस खरीदा' जैसी सहज हास्य रचना प्रस्तुत की। गिरीश लोवलेकर ने हास्य गीत प्रस्तुत किया। रतीश गोहिल, एम. आर. घुले, रघुवंशी, डी. आर. कौल और ने अपनी रोचक प्रस्तुतियों से श्रोताओं को भरपूर आनंदित किया। प्रतिभागियों का उत्साह और सुधि श्रोताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति वाकई प्रशंसनीय रही।

यूएई में तीन भारतीयों के घायल होने पर भारत नाराज

तेहरान (एजेंसी)। यूएई के फुजैराह में ऑयल पोर्ट पर हुए हमले को लेकर भारत ने नाराजगी जताई है। सरकार ने कहा कि तीन भारतीयों का घायल होना गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत हिंसा बंद करने और आम लोगों को निशाना न बनाने को कहा है। भारत ने कहा कि हालात को संभालने का सही रास्ता बातचीत और कूटनीति है, ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए।

बिहार में 7 मई को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

● सम्राट की टीम में शामिल हो सकते हैं युवा विधायक

पटना (एजेंसी)। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख का ऐलान हो गया है। नई सरकार के गठन के बाद अब 7 मई को नई कैबिनेट का गठन होगा। अभी तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्री वियज चौधरी और बिजेंद्र यादव के ही पास सारे विभागों की जिम्मेदारी थी। हालांकि, अब नए लोगों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदापी सौंपी जाएगी। इससे जनता के हितों में किए जा रहे कार्यों को और गति मिलने की संभावना है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार गांधी मैदान में होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे।

डिफेंस की तरह अब नॉलेज कॉरिडोर करें तैयार : राजनाथ

● रक्षामंत्री बोले- हमें सरप्राइज एलिमेंट पर प्रो-ऐक्टिव होकर काम करना है

प्रयागराज (एजेंसी)। प्रयागराज में सोमवार को उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी (नॉर्थ टेक सिम्पोजियम) 2026 की शुरूआत हो गई। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा- डिफेंस कॉरिडोर की तरह नॉलेज कॉरिडोर तैयार करें। उन्होंने कहा-ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को हमारी ताकत का एहसास हो गया है। उन्होंने कहा- मैं प्रो-एक्टिव तैयारी की बात कर रहा हूं। वो है सरप्राइज एलीमेंट। हमें ऐसी क्षमताएं भी विकसित करनी है जो जरूरत पड़ने हम ऐसा प्रहार कर सकें जिससे दुश्मन सरप्राइज हो जाए। मुझे पता है कि हमारी सेना इस ओर काम कर रही हैं।

भारत की अग्नि मिसाइल का दम, खौफ में ड्रैगन

● चीन ने तिब्बत में तैनात किया सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम ● सैटेलाइट गिराने में भी सक्षम

बीजिंग (एजेंसी)। रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन ने एचक्यू-29 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारत की सीमा से सटे तिब्बत में तैनात किया है। बताया जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के साथ ही यह सिस्टम निचली कक्षा में स्थित सैटेलाइट को नष्ट करने में भी सक्षम है। चीनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एचक्यू-29 लॉन्चरों और इंटरसेप्टर मिसाइलों को ट्रेन से ले जाते दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि बीजिंग का यह नया

हथियार चीनी रणनीतिक बलों भीतर ऑपरेशनल स्थिति में पहुंच गया है। एचक्यू-29 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आधिकारिक तौर पर सितम्बर 2025 में बीजिंग में हुए एक मिलिट्री परेड के दौरान दुनिया के सामने पेश किया गया था। बताया जाता है कि इसे उसी साल की शुरुआत में सेना में शामिल कर लिया था।

चीन को भारत की अग्नि-5 मिसाइल का खौफ

चीन के इस सिस्टम की तैनाती की खबर ऐसे समय में आई है, जब भारत का अग्नि-6 मिसाइल कार्यक्रम पूरी तरह तैयार है। पिछले सप्ताह ही डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी. कामत ने कहा कि कार्यक्रम पूरी तरह तैयार है। हमें सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। 12000 किमी की क्षमता वाली यह मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। यह एक साथ कई वॉरहेड्स ले जा सकती है।

● खुद मार ली पैर में कुल्हाड़ी, असम पूरे भारत के लिए सबक है

कांग्रेस पर चिपक गया 'मियां' मुस्लिम वाला लेबल

गुवाहाटी (एजेंसी)। असम में कांग्रेस को जिस तरह का झटका लगा है, उससे उसकी राजनीति की जड़ें हिल चुकी हैं। राज्य में पार्टी के दोनों शीर्ष नेता गौरव गोगोई और देबब्रत सैकिया अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए। कांग्रेस ने असम की सत्ता में वापसी के लिए प्रचार में दो तरह के हथियार अपनाए थे, दोनों ही पूरी तरह से फेल हो गए। अगर असम में कांग्रेस के चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो यह पूरे भारत के लिए एक सबक की तरह है। असम में चुनाव प्रचार के दौरान गौरव गोगोई की अगुवाई में पार्टी ने बीजेपी पर अटैक के लिए दो तरह के हथियार का इस्तेमाल किया। एक तो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार पर निजी हमले शुरू किए। दूसरा जुबीन गर्ग की मौत पर चुनावी रोटियां सेंकने की कोशिश की। लेकिन, यह दोनों ही मुद्दा बैकफायर कर गया।

● **मुस्लिम-बहुल सीटों तक सिमटी कांग्रेस-** असम में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार तथ्य यह है कि ये सभी सीटें मुस्लिम-बहुल हैं। मतलब, कांग्रेस को वो सीटें मिली हैं, जो कभी वो इत्र कारोबारी बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के साथ साझा किया करती थी। एआईयूडीएफ के इत्र की खुशबू फीकी पड़ी है तो कांग्रेस को उन सीटों पर सिर छिपाने की जगह मिली है।

● **खुद ही 'मियां-मुस्लिम' पार्टी बन गई कांग्रेस!-** मुस्लिम बहुल सीटों से एआईयूडीएफ का बाहर होना और कांग्रेस की पकड़ मजबूत होने का मतलब साफ है कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा असम के वोटरों को लगातार जो संदेश देना चाह रहे थे, उसमें वो सफल हो गए। उन्होंने कांग्रेस को 'मियां' पार्टी का तमगा पहनाना चाहा और कांग्रेस ने खुद ही वह तमगा अपने गले में डाल लिया।

हिंदुओं और मूल आदिवासियों से दूर हुई कांग्रेस

असम में 'मियां' शब्द बांग्लादेश के बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। कांग्रेस 'मियां' मुसलमानों की पार्टी है, इस ठप्पे ने उसे असम के मूल आदिवासियों और हिंदू वोटरों से पूरी तरह से दूर कर दिया। रही-सही कसर 2023 में हुए परिसीमन ने पूरी कर दी। परिसीमन के बाद असम में मुस्लिम-बहुल विधानसभा सीटों की संख्या 35 से घटकर 22 रह गई है। इनमें से इस बार 19 कांग्रेस के खाते में गई है, 2 पर एआईयूडीएफ जीता है और 1 पर टीएमसी का खाता खुला है।

22 देशों के बीच भारत का जलवा

मोजियांग में भोपाली ट्विन्स के बॉलीवुड डांस पर झूम उठा चीन

भोपाल (नप्र)। चीन के युन्नान प्रांत में हाल ही में आयोजित 20वें इंटरनेशनल ट्विन्स फेस्टिवल-2026 में भारत का दबदबा देखने को मिला। भोपाल के ट्विन्स क्लब ने इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर न केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि अपनी शानदार प्रस्तुतियों से 10 हजार से अधिक दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

30 अप्रैल से 4 मई तक चला जश्न

क्लब के अध्यक्ष अभिषेक खरे के नेतृत्व में भारतीय दल चीन पहुंचा था। इस टीम में बॉलीवुड अभिनेता और डांसर जोड़ी पराग-प्रयास चौधरी के साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रकृति-श्रृष्टि कुशवाहा शामिल थीं। इन दोनों जोड़ियों ने जब बॉलीवुड गानों के मेडली पर डांस शुरू किया, तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

लिम्का बुक में दर्ज है क्लब की पहचान- बता दें कि भोपाल का यह ट्विन्स क्लब कोई आम क्लब नहीं है, बल्कि इसका नाम वर्ष 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। साल 2014 से यह क्लब लगातार चीन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस साल की थीम 'ट्विन्स फार पेस एण्ड लव' रखी गई थी।

22 देशों के 700 से ज्यादा जुड़वां हुए शामिल

इस फेस्टिवल में अमेरिका, इंग्लैंड, मलेशिया और श्रीलंका समेत 22 देशों के 200 से अधिक और खुद चीन के 500 से अधिक जुड़वां प्रतिभागी शामिल हुए।

अभिषेक खरे, अध्यक्ष (ट्विन्स क्लब भोपाल) ने बताया कि भारतीय ट्विन्स पिछले 10 सालों से यहां आ रहे हैं। इससे चीन के लोगों और अन्य देशों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हुए हैं। यहां आना किसी सपने के सच होने जैसा है।

वेशभूषा ने जीता सबका दिल

परेड के दौरान जब भारतीय टीम पारंपरिक ड्रेस में उतरी, तो विदेशी प्रतिभागी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्साहित दिखे। पराग और प्रयास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यहां आकर ऐसा लगा जैसे हम अपने वैश्विक परिवार से मिल रहे हैं। वहीं, प्रकृति और श्रृष्टि ने आयोजन की भव्यता को देखकर अपनी खुशी जाहिर की।

अब भारत में भी मनेगा ट्विन्स उत्सव

चीन में मिली इस सफलता के बाद अभिषेक खरे ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में ट्विन्स क्लब, भोपाल और ट्विन्स इंडिया मिलकर भारत में भी इसी तरह का एक भव्य इंटरनेशनल ट्विन्स फेस्टिवल आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।

भोपाल में ब्लू लाइन मेट्रो के लिए काटे गए दशकों पुराने पेड़

पुरानी विधानसभा के सामने चल रहा सफाई का काम

भोपाल (नप्र)। झीलों के शहर भोपाल में विकास की रफ्तार अब पेड़ों पर भारी पड़ने लगी है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के ब्लू लाइन एलिवेटेड कॉरिडोर का रास्ता साफ करने के लिए ऐतिहासिक मिंटो हॉल यानी पुरानी विधानसभा के ठीक सामने लगे दशकों पुराने छायादार पेड़ों को काट दिया गया है।

मुसाफिरों का आसरा खत्म- ये पेड़ महज हरियाली का हिस्सा नहीं थे, बल्कि पास के व्यस्त बस स्टॉप पर खड़े यात्रियों के लिए तपती गर्मियों में कुदरती छतरी का काम करते थे। अब वहां सिर्फ सन्नाटा और कांक्रीट का मलबा नजर आता है।

इन पेड़ों के नीचे खड़े होकर हम बस का इंतजार करते थे। अब यहां सिर्फ धूप बची है। मेट्रो आए यह अच्छी बात है, लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि नए पेड़ कब और कहां लगेंगे?

सब नियमों के तहत हुआ- पेड़ों की कटाई को लेकर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि यह काम जरूरी था। एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए खाली जगह की जरूरत होती है। अफसरों के मुताबिक, पेड़ों को काटने के लिए सभी जरूरी कानूनी अनुमतियां ली गई थीं। नुकसान की भरपाई के लिए अब कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा पौधारोपण की जिम्मेदारी दी गई है।

ब्लू लाइन प्रोजेक्ट : एक नजर में

यह कटाई 12.9 किलोमीटर लंबे ब्लू लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह लाइन भदभदा चौराहे से शुरू होकर रत्नागिरी तिराहे तक जाएगी।

कॉरिडोर का नाम	ब्लू लाइन
कुल दूरी	12.9 किलोमीटर
स्टेशनों की संख्या	13 एलिवेटेड स्टेशन
समय सीमा	2025 में काम शुरू, 3 साल का लक्ष्य
रूट	भदभदा से रत्नागिरी तिराहा

विकास बनाम पर्यावरण

पर्यावरणविदों का मानना है कि भले ही काटे गए पेड़ों की संख्या कम हो, लेकिन ऐतिहासिक इमारतों के पास से हरियाली का गायब होना चिंताजनक है। यह मामला एक बार फिर शहर के बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के बीच के तनाव को उजागर करता है। जहां एक ओर मेट्रो शहर में यातायात को आधुनिक बनाएगी, वहीं दूसरी ओर पुराने पेड़ों के कटने से भोपाल की ग्रीन सिटी वाली छवि पर सवाल उठ रहे हैं।

अमेरिका जा रही थी पत्नी विवाद के बाद कारोबारी पति ने खुद को मारी गोली

इंदौर (नप्र)। लसूड़िया थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां शांति निकेतन टाउनशिप में रहने वाले 62 वर्षीय हार्डवेयर कारोबारी सुधीर पाटनी ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि घटना से पहले उनका अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया।

अमेरिका में रहते हैं बच्चे

इंदौर पुलिस के अनुसार सुधीर पाटनी अपने परिवार के साथ शांति निकेतन में रहते थे। घर में उनकी पत्नी और बुजुर्ग माता-पिता मौजूद थे जबकि बेटा और बेटी अमेरिका में रहते हैं। बताया जा रहा है कि पत्नी सोमवार को अमेरिका जाने वाली थीं, जहां उनकी बेटी के कार्यक्रम में शामिल होना था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कुछ समय से तनाव चल रहा था।

रविवार रात हुई कहासुनी- रविवार देर रात दोनों के बीच एक बार फिर कहासुनी हुई। विवाद के बाद दोनों अलग-अलग कमरों में चले गए। इसी दौरान गुस्से और तनाव में आकर सुधीर पाटनी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि कमरे के अंदर तीन से ज्यादा फायर की आवाजें सुनी गईं।

कमरे में लाश देखकर रह गईं सन्न

घटना के समय उनके माता-पिता घर की निचली मंजिल पर थे। कुछ देर बाद जब पत्नी अपने कमरे से बाहर आईं तो उन्हें कोई हलचल नहीं दिखी। सोमवार सुबह करीब तीन बजे जब वह बैग लेने के लिए उनके कमरे में पहुंचीं तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गईं। सुधीर पाटनी जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे और उनकी कनपटी पर गोली लगी हुई थी।

कोई सुसाइड नोट नहीं मिला- सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।

विक्रमोत्सव 2026 को मिले दो अवॉर्ड

उज्जैन। मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव को इस वर्ष गोल्ड एवं सिल्वर अवॉर्ड मिले है। नई दिल्ली में 1 और 2 मई 2026 को आयोजित नौ आफ इंडिया कान्क्लेव 2026 में विक्रमोत्सव 2026 को सांस्कृतिक लाइव इवेंट ऑफ द ईयर में गोल्ड अवार्ड कल्चरल लाईव इवेंट्स ऑफ द ईयर गोल्ड अवॉर्ड तथा लाइव इवेंट में सर्वश्रेष्ठ शासकीय सहभागिता की श्रेणी में सिल्वर अवॉर्ड बेस्ट गवर्नमेंट इंटीग्रेशन फार ए लाव इवेंट सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। वाऊ की टीम यह अवॉर्ड भोपाल आकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को प्रदान करेगी।

मालूम हो कि विक्रमोत्सव दुनिया का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला सांस्कृतिक आयोजन है। जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ बिजनेस इवेंट भी शामिल है। यह कार्यक्रम इवेंट फैक्स मीडिया आयोजित किया गया था, जो देश के इवेंट एवं एक्सपीरिएंशियल मार्केटिंग क्षेत्र का अग्रणी प्लेटफॉर्म है। यह अवॉर्ड् वाव लाईव अवार्ड के अंतर्गत प्रदान किए गए, जो देश में कॉन्सर्ट, फेस्टिवल, टूर और लाइव इवेंट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रचनाकारों और दूरदर्शियों को सम्मानित करते हैं। इस वर्ष 300 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई, जो इस क्षेत्र के बढ़ते विस्तार, विविधता और संभावनाओं को दर्शाती हैं। विशेषज्ञ जूरी पैनल द्वारा इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया गया। जिसके आधार पर सम्मानों की घोषणा की गयी। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार एवं महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने कहा कि विक्रमोत्सव 2026 को मिले गोल्ड एवं सिल्वर अवॉर्ड मध्यप्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। यह सम्मान न केवल मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह मध्यप्रदेश की पारंपरिक एवं आधुनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरासत से विकास के मंत्र को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश निरंतर कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर ऐसे आयोजनों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सशक्त और समृद्ध बनाने का कार्य कर रही है। विक्रमोत्सव हमारी परंपराओं, मूल्यों और नवाचार का जीवंत उत्सव बन गया है। यह उपलब्धि हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी तथा भविष्य में मध्यप्रदेश को सांस्कृतिक क्षेत्र में नई ऊँचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। तिवारी बताया कि इसके पहले विक्रमोत्सव 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा लांगस्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। वाउ अवॉर्ड एशिया 2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवॉर्ड मिल चुका है। वर्ष 2024 में विक्रमोत्सव को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड मिला था। उन्होंने बताया कि सृष्टि सृजनकर्ता महादेव के भव्य-दिव्य महाशिवरात्रि उत्सव से विक्रमोत्सव 2026 का आरंभ कर सृष्टि निर्माण दिवस वर्ष प्रतिपदा से होते हुए पंच महाभूतों में अतिविशिष्ट जल तत्व के संरक्षण, संवर्धन के लिए विशिष्ट रूप से नियोजित जल गंगा संवर्धन अभियान का आयोजन होगा।

समितियां लोकतंत्र की आत्मा, इसे प्रभावी बनाना हमारा कर्तव्य : तोमर

जयपुर, भोपाल। समिति प्रणाली की समीक्षा हेतु गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की द्वितीय बैठक राजस्थान विधानसभा, जयपुर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की।

अपने उद्बोधन में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि समिति प्रणाली वास्तव में लोकतांत्रिक शासन का वह आधारभूत स्तंभ है, जो नीति निर्माण को केवल सैद्धांतिक प्रक्रिया न रहने देकर उसे व्यवहारिक और उत्तरदायी बनाता है। समिति प्रणाली केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जीवंत आत्मा है। हम सभी पर यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम इस प्रणाली को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखें, बल्कि इसे एक सशक्त, सक्रिय और परिणामोन्मुख माध्यम के रूप में विकसित करें। जब समितियाँ सशक्त होंगी, तो विधायिका सशक्त होगी; और जब विधायिका सशक्त होगी, तब लोकतंत्र और अधिक दृढ़, विश्वसनीय और जन-केन्द्रित बनेगा। मुझे गर्व है कि मध्यप्रदेश विधानसभा समिति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा

जनकल्याण में इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

श्री तोमर ने कहा कि हमारा लोकतंत्र केवल संविधान के प्रावधानों से ही नहीं चलता, बल्कि उन जीवंत संस्थाओं से भी संचालित होता है, जो जन-आकांक्षाओं को नीतियों में रूपांतरित करती हैं। विधायिका इस प्रक्रिया का केंद्र है, और विधायिका की प्रभावशीलता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है– समिति प्रणाली। समिति प्रणाली केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है। यह हमें यह सिखाती है कि संवाद, सहमति और सहयोग के माध्यम से ही हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम समिति प्रणाली को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाएँ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रणाली केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि वास्तव में लोकतंत्र की शक्ति का आधार बने। यदि हम इसे सही दिशा में ले जाने में सफल होते हैं, तो यह न केवल हमारी विधायिकाओं को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि जनता के विश्वास को भी सुदृढ़ करेगा।

छह राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की भागीदारी- बैठक में पश्चिम बंगाल को छोड़ कर सात में से छह राज्यों - मध्य प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, उड़ीसा विधान सभा की अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाढ़ी और सिक्किम विधान सभा के अध्यक्ष श्री मिंगमा नोरबू शेरपा शामिल हुए। गौरतलब है कि समिति की पहली बैठक 14 जुलाई 2025 को मध्यप्रदेश विधानसभा में आयोजित हुई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव उपस्थित हुए थे। इस बैठक में समिति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा जनकल्याण में इसकी भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ था।

म.प्र. मदरसा बोर्ड की परीक्षा 10वीं-12वीं उर्दू माध्यम के ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी

भोपाल (नप्र)। म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी (उर्दू माध्यम) परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथियों का शैक्षणिक कैलेण्डर जारी किया गया है। छात्र स्वंय अथवा अध्ययन केन्द्रों दोनों माध्यमों से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। छात्रों द्वारा सीधे ऑनलाइन आवेदन करने पर अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी/ मदरसा प्रभारी से ऑनलाइन आवेदन पत्र का सत्यापन कराकर निर्धारित तिथियों में म.प्र. मदरसा बोर्ड को भेजना होगा। क्रेडिट योजनांतर्गत सम्मिलित होने वाले छात्रों को संबंधित मंडल से अंकसूची का सत्यापन कराकर सत्यापन एवं मूल अंकसूची परीक्षा आवेदन के साथ भेजना होगा। स्वंय अंकसूची का सत्यापन न कराने वाले छात्रों को बोर्ड द्वारा निर्धारित सत्यापन शुल्क 1000/-ऑनलाइन/चालान के माध्यम से जमा करना होंगे। शैक्षणिक कैलेण्डर एवं शुल्क संरचना म.प्र. मदरसा बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने मंत्रालय में विकास कार्यों की समीक्षा की।

सिंगरौली की शर्मनाक तस्वीर, अस्पताल के गेट पर तड़पती रही गर्भवती, ताले ने छीन ली नवजात की सांसें

सिंगरौली (नप्र)। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खबर आई है, जिसने सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। चितरंगी इलाके में एक गर्भवती महिला दर्द से कराहती रही, अपनों ने मदद के लिए उपस्वास्थ्य केंद्र का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां मिला तो सिर्फ एक बड़ा सा ताला और सन्नाटा। मजबूरी में अस्पताल के गेट पर ही डिलीवरी करानी पड़ी, लेकिन अफसोस कि दुनिया देखने से पहले ही उस मासूम की सांसें थम गईं।

दावों की खुली पोल- चितरंगी के लमसरई केंद्र की हालत देखकर ऐसा लगा मानो यह कोई वीरान खंडहर हो। चारों तरफ लंबी घास और गेट पर जंग लगा ताला। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां डॉक्टर या नर्स के दर्शन तो 'ईद के चांद' की तरह कभी-कभार ही होते हैं।

पीड़ित ग्रामीण महिला ने कहा कि हम गरीब लोग हैं साहब, न पास में गाड़ी है न पैसा। इमरजेंसी में जब अस्पताल के ताले बंद मिलते हैं, तो सिवाय भगवान को याद करने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता।

हर केंद्र की एक ही कहानी- टीम जब बिहरा, बिंदुल, जिर और पोड़ी पाठ जैसे केंद्रों पर पहुंची, तो वहां भी कमोबेश यही नजारा था। कहीं बिल्डिंग तो खड़ी है पर अंदर स्टाफ का अता-पता नहीं, तो कहीं लाइट और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक गायब हैं।

कलेक्टर का कड़ा रुख- मामला तूल पकड़ते ही प्रशासन की नींद खुली है। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ कहा, मामला गंभीर है।

90-डिग्री फ्लाईओवर के बाद ऐशबाग में एक और 'अधूरा अजूबा'

रेलवे की बाउंड्री में फंसा पब्लिक टॉयलेट

भोपाल (नप्र)। राजधानी के ऐशबाग इलाके में पहले से ही 90-डिग्री वाला अधूरा फ्लाईओवर सिस्टम की नाकामी का गवाह बना खड़ा है। अब इसी फेहरिस्त में एक और नया मामला जुड़ गया है। यहां नगर निगम ने लाखों रुपये खर्च कर एक सार्वजनिक शौचालय बनवाया, लेकिन अब वह किसी काम का नहीं रहा। वजह यह है कि रेलवे ने अपनी जमीन को सुरक्षित करने के लिए शौचालय के ठीक आगे एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी है, जिससे इसके अंदर जाने का रास्ता ही खत्म हो गया।

चेतावनी को किया अनसुना

स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने बताया कि जहां यह शौचालय बनाया गया है, वहां पहले कचरे का ढेर लगा रहता था। बीएमसी ने सफाई के मकसद से यहां शौचालय बनाना शुरू किया। लोगों ने शुरुआत

में ही अफसरों को आगाह किया था कि यह जमीन रेलवे की है और बेहतर होगा कि पास ही निगम की अपनी खाली जमीन (पुराने वाटर टैंक के पास) पर इसे बनाया जाए। लेकिन, अधिकारियों ने लोगों की बात को अनसुना कर दिया और निर्माण कार्य जारी रखा।

रेलवे ने खींच दी दीवार

पिछले दो हफ्तों के भीतर रेलवे ने अपनी सीमा तय करते हुए वहां पक्की दीवार खड़ी कर दी। नतीजा यह हुआ कि नया बना शौचालय अब रेलवे परिसर के अंदर एक बंद डिब्बे की तरह फंसा हुआ है। स्थानीय व्यापारियों ने कहा यह जनता के पैसे की सीधी बर्बादी है। जब जमीन हमारी थी ही नहीं, तो वहां निर्माण क्यों कराया गया? अब न तो यहां कोई जा सकता है और न ही इसका कोई उपयोग है। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है?

अफसरों ने साधी चुप्पी

इस पूरे विवाद पर वार्ड 40 की पार्षद मसर्रत और बीएमसी के कार्यपालन यंत्री ए.के. साहनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं, अधीक्षण यंत्री आर.आर. जरोलिया ने बस इतना कहा कि वे शहर से बाहर हैं और वापस आकर मामले की जांच करेंगे।

नियोजन की कमी का नया स्मारक

ऐशबाग के लिए यह कोई नई बात नहीं है। यहां का फ्लाईओवर पहले से ही गलत प्लानिंग की भेंट चढ़ा हुआ है। अब यह शौचालय भी उसी कड़ी का हिस्सा बन गया है। बिना किसी दूरदर्शिता के शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया है कि अफसर जनता के टैक्स के पैसे को लेकर कितने लापरवाह हैं।

संपादकीय

किसका समर्थन लेंगे विजय

तमिल अभिनेता थलपगति विजय जोसेफ की पार्टी तमिल वेत्री कझघम (टीवीके) ने अपने पहले ही चुनाव में तमिलनाडु में बंपर जीत हासिल तो कर ली है, लेकिन वह बहुमत से दस सीटें पीछे रह गई है। ऐसे में सवाल यह है कि विजय सरकार बनाने के लिए किन दूसरे दलों का समर्थन लेना चाहेंगे और अपनी राजनीति की दिशा कौन सी रखना चाहेंगे। तमिनलनाडु विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें मतदाताओं ने किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। ऐसे में राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बन रही है। सरकार बनाने के लिए विजय की पार्टी को 234 सीटों वाली विधानसभा में 118 सीटें चाहिए। विजय के सामने दिक्कत यह है कि वो द्रविड़ राजनीति करने वाले दोनों दलों पूर्व में सत्तारूढ़ डीएमके और एआईडीएमके के खिलाफ चुनाव लड़कर जीते हैं। ऐसे में डीएमके के साथ जाने की तो कोई संभावना नहीं है। दूसरा विकल्प कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने का है। जैसे कि डीएमके गठबंधन में शामिल कांग्रेस के 5, एडीएमके का 1 तथा अन्य 8 का समर्थन लेकर सरकार बनाए। लेकिन कई छोटे दलों के समर्थन से बनी सरकार कितने दिन चलेगी, कहना मुश्किल है। क्योंकि कोई कभी भी रूठ सकता है। दूसरे, इन सभी दलों का जोड़ 14 होता है, जो साधारण बहुमत से केवल 4 ज्यादा है। ऐसे में सरकार पर गिरने की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। हालांकि विजय की पार्टी के कुछ नेताओंका कहना है कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है। विजय के पिता एक बयान में कांग्रेस का समर्थन लेने की बात कही है, लेकिन केवल कांग्रेस के समर्थन से बात नहीं बनती।क्योंकि उसके पास मात्र 5 विधायक हैं। तीसरा विकल्प एआईएडीएमके गठबंधन का समर्थन लेना है। एआईएडीएमके केन्द्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और इस बार राज्य में भाजपा का एक विधायक भी जीता है। अगर विजय एआईएडीएमके गठबंधन का समर्थन लेते हैं तो उन्हें 73 विधायकों का समर्थन मिल जाएगा। जिसमें अकेले एआईएडीएमके के 59 विधायक हैं। इस गठबंधन को साथ लेने से विजय को केन्द्र सरकार से भी मदद मिलेगी। विस चुनाव में अच्छी सफलता के लिए विजय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फोन पर बधाई भी दी थी, जिसमें काफी संकेत छिपे हुए हैं। अगर विजय अलग राह चुनते हैं तो वो सरकार तो बना लेंगे, लेकिन केन्द्र से उन्हें अपेक्षित सहयोग मिले, यह जरूरी नहीं है। हालांकि एआईएडीएमके के दबाव में उन्हे द्रविड़ राजनीति के हिसाब से चलता पड़ सकता है। ऐसे में विजय के सामने यह यक्ष प्रश्न है कि वह सरकार बनाने के लिए किसका समर्थन लें। जहां तक भाजपा की बात है तो उसके पास केवल एक विधायक है, लेकिन भाजपा का असली लक्ष्य सनातन और हिंदू विरोधी डीएमके को सत्ता से बाहर करना था, वह पूरा हो गया है। ऐसे में टीवीके अलग राह चुनती भी है तो भाजपा उसे पीछे समर्थन देगी। क्योंकि उसका दीर्घकालीन उद्देश्य सनातन और हिंदू विरोधी नरेटिव को खत्म करना है। सरकार बनाने के साथ साथ विजय के सामने चुनाव में किए गए वादे पूरा करने की भी चुनौती रहेगी। टीवीके अपने चुनावी घोषणापत्र में जनता से कई बड़े-बड़े वादे किए थे। मसलन परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 2500 रुपये की सहायता, 60 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए समान योजनाओं के लाभार्थियों को छोड़कर हर महीने 2500 रुपये की सहायता, गरीब परिवारों दुल्हनों को आठ ग्राम सोना और रेशमी साड़ी तथा पांच लाख नई सरकारी नौकरियां, विद्यार्थियों के लिए पांच लाख वेतनयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना, बेरोजगार स्नातकों को प्रतिमाह 4 हजार रुपये भत्ताऔर उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देना शामिल है।

रणनीति बनाम अहंकार, और कमजोर होती जड़ें

ममता बनर्जी के पतन के पीछे अनेक कारण हैं। पन्द्रह वर्षों की सत्ता का घमण्ड, तुष्टिकरण की राजनीति का अतिरेक, आरजी कर कांड जैसे जघन्य प्रकरण में न्याय की विफलता और अवैध घुसपैठियों के प्रश्न पर ढुलमुल रवैया – इन सबने मिलकर 'दीदी' के जनाधार में वह दरार पैदा की जिसे भाजपा ने कुशलतापूर्वक चौड़ा किया। भाजपा नेता विरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि जनता ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे अवैध प्रवासियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। ममता बनर्जी की पराजय केवल एक चुनावी हार नहीं है; यह उस राजनीतिक अहंकार की हार है जो सुरक्षा, न्याय और राष्ट्रीय अस्मिता को वोट-बैंक की बलिवेदी पर चढ़ाती रही।

नजरिया

जयदेव राठी

लेखक एडवोकेट हैं।

4 मई 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुच्चेरी। इन पाँच राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेश में एक साथ आए चुनाव परिणामों ने देश की राजनीतिक भूगोल को हिलाकर रख दिया। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में पहली बार सत्ता का सूर्योदय देखा, वहीं तमिलनाडु में एक अभिनेता ने राजनीतिक दलों की जड़ें हिला दीं, केरल में कांग्रेस-नेतृत्व वाले गठबंधन ने वामदल की 'तिकड़ी' की आकांक्षा तोड़ी, असम में भाजपा ने हैट्रिक लगाई और पुदुच्चेरी में एनडीए ने अपना परचम लहराया। यह परिणाम केवल राज्यों की राजनीति की कहानी नहीं है, यह 2029 के लोकसभा चुनावों की पूर्वपीठिका है। सबसे बड़ा और सर्वाधिक चर्चित उलटफेर पश्चिम बंगाल में हुआ। भाजपा ने 148 के बहुमत के आँकड़े को पार कर लिया और यह परिणाम 'हिन्दू एकजुटता' का प्रतिफल बताया गया। नवीनतम रुझानों के अनुसार भाजपा 199 सीटों पर आगे है जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस मात्र 88 सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव में 92.47 प्रतिशत की असाधारण मतदान-भागीदारी दर्ज हुई जो जनता के आक्रोश और परिवर्तन की तड़प का प्रमाण है।

ममता बनर्जी के पतन के पीछे अनेक कारण हैं। पन्द्रह वर्षों की सत्ता का घमण्ड, तुष्टिकरण की राजनीति का अतिरेक, आरजी कर कांड जैसे जघन्य प्रकरण में न्याय की विफलता और अवैध घुसपैठियों के प्रश्न पर ढुलमुल रवैया – इन सबने मिलकर 'दीदी' के जनाधार में वह दरार पैदा की जिसे भाजपा ने कुशलतापूर्वक चौड़ा किया। भाजपा नेता विरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि जनता ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वे अवैध प्रवासियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। ममता बनर्जी की पराजय केवल एक चुनावी हार नहीं है; यह उस राजनीतिक अहंकार की हार है जो सुरक्षा, न्याय और राष्ट्रीय अस्मिता को वोट-बैंक की बलिवेदी पर चढ़ाती रही। ममता बनर्जी ने परिणाम को संदिग्ध बताने का प्रयास किया, किन्तु यह हताशे में डूबे उस नेतृत्व का अन्तिम प्रतिरोध था जो जनादेश की भाषा पढ़ नहीं पाया। दक्षिण में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपने कोलथूर विधानसभा क्षेत्र से टीवीके (तमिलागा वेट्री कझगम) के प्रत्याशी वी.एस. बाबू से पराजित हो गए – यह चुनाव का सर्वाधिक चौंकाने वाला क्षण था। तमिलनाडु में टीवीके 109 सीटों के साथ आगे है, अन्नाद्रमुक 71 सीटों के साथ दूसरे और द्रमुक मात्र 54 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई है। अभिनेता विजय द्वारा स्थापित टीवीके ने उस राजनीतिक ध्रुवीकरण का लाभ उठाया जो द्रमुक की सनातन-विरोधी टिप्पणियों और केन्द्र सरकार के विरुद्ध टकराव की नीति से उत्पन्न हुआ था। स्टालिन के पुत्र उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने वाला विवादास्पद बयान तमिल जनता के एक बड़े वर्ग को स्वीकार नहीं हुआ।

जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक आस्था पर प्रहार करने वाली राजनीति का कोई स्थायी भविष्य नहीं है। कोयम्बटूर जैसे क्षेत्र जो अन्नाद्रमुक के गढ़ माने जाते थे, वहाँ टीवीके का वर्चस्व स्थापित हो गया। तमिलनाडु की जनता ने पुराने राजनीतिक ढाँचे को नकारते हुए नए विकल्प को आत्मसात किया है।

केरल में कांग्रेस-नेतृत्व वाले यूडीएफ ने बहुमत का आँकड़ा पार कर लिया और वह 100 सीटों पर आगे है जबकि वामदल का एलडीएफ मात्र 35 सीटों तक सिमट गया। यह वामपंथी मोर्चे की ऐतिहासिक पराजय है जो लगातार तीसरे कार्यकाल का स्वप्न देख रहा था। केरल में पिनाराई विजयन सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश के अनेक कारण थे। सबरीमाला विवाद, स्वर्ण तस्करी का कांड और जन-विरोधी नीतियाँ, इन सब पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया। केरल में कांग्रेस की इस वापसी का एक विशेष महत्त्व है। यह उन विश्लेषकों को करारा जवाब है जो कांग्रेस को दक्षिण में भी अप्रासंगिक घोषित करने पर आमादा थे। हालाँकि यह जीत कांग्रेस की अपनी शक्ति से कम और वाम सरकार की विफलताओं का प्रतिफल अधिक है, इस बात को पार्टी नेतृत्व को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। असम में एनडीए 126 में से 99 सीटों पर आगे है और मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्व सरमा एक प्रचण्ड जनादेश की ओर अग्रसर हैं जबकि कांग्रेस-नेतृत्व गठबंधन मात्र 25 सीटों पर सिमट गया है। स्वयं मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्व सरमा ने जलुकबारी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी बिदिशा नेओ को 80,000 से अधिक मतों के भारी अन्तर से पराजित किया।

असम में भाजपा की तीसरी जीत का केन्द्रीय कारण है, अवैध घुसपैठ का प्रश्न, विकास की ठोस उपलब्धियाँ और हिमन्त का निर्णायक नेतृत्व। कांग्रेस ने धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप लगाए, किन्तु असमिया जनता के मन में बंग्लादेशी घुसपैठ का भय एक वास्तविक और गहरी चिन्ता है जिसे नकारकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। यह परिणाम यह भी सिद्ध करता है कि उत्तर-पूर्व में भाजपा ने अपनी जड़ें कितनी गहरी जमा ली हैं। पुदुच्चेरी में मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी की एआईएनआरसी-नेतृत्व वाली एनडीए 15 सीटों पर आगे है जबकि कांग्रेस-डीएमके गठबंधन 11 सीटों पर संघर्ष कर रहा है। रंगास्वामी स्वयं थट्टनचावड़ी से 4,441 मतों के अन्तर से विजयी हुए। छोटे से इस केन्द्रशासित प्रदेश में भाजपा गठबंधन की जीत यह संकेत देती है कि दक्षिण में भी एनडीए का विस्तार केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है। इन पाँच परिणामों को एक साथ देखने पर कुछ स्पष्ट तथ्य उभरकर आते हैं। पहला, भाजपा की संगठनात्मक क्षमता और प्रधानमंत्री मोदी की अपील अभी भी अजेय बनी हुई है। बंगाल जैसे राज्य में जहाँ भाजपा को 'बाहरी' बताकर दशकों से दरकिनार किया जाता रहा, वहाँ बहुमत से सरकार बनाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। दूसरा, कांग्रेस का राष्ट्रीय जनाधार क्षरण जारी है। केरल में राहत अवश्य मिली, किन्तु यह वाम-विरोधी लहर का लाभ है, कांग्रेस की अपनी पुर्नस्थापना नहीं। बंगाल और असम में पार्टी का प्रदर्शन दयनीय रहा। तीसरा, सनातन और सांस्कृतिक प्रश्नों पर किया गया प्रहार जनता को स्वीकार्य नहीं है, चाहे वह तमिलनाडु में स्टालिन परिवार का बयान हो या बंगाल में ममता का तुष्टिकरण। चौथा, विजय जैसे नए नेता का उभरना यह बताता है कि दक्षिण भारत में जनता परिवर्तन के लिए आतुर है और वह पुराने राजनीतिक वंशवाद को चुनौती देने के लिए तैयार है।

यह जनादेश 2029 के लोकसभा चुनावों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 2026 के ये चुनाव 2029 की केन्द्र सरकार के निर्माण के लिए एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे थे। भारत की जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह विकास, सुरक्षा और सांस्कृतिक सम्मान के प्रश्नों पर किसी के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। नेताओं का अहंकार, वंशवाद और तुष्टिकरण, इन तीनों को जनता ने एक ही दिन में उत्तर दे दिया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भाजपा को दिलाई जीत

चुनाव

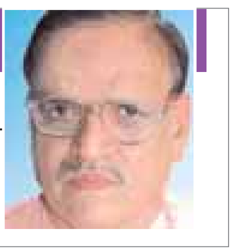

प्रमोद भार्गव

लेखक पत्रकार हैं।

पश्चिम बंगाल,असम, तमिलनाडु,केरल और पुंडुचेरी के परिणाम आ गए हैं। बंगाल में भाजपा ने तृणमूल मुखिया ममता बनर्जी को बड़ा झटका देकर बंगाल को स्पष्ट बहुमत के साथ झटक लिया है। बंगाल का यह नतीजा उन पाखंडी बौद्धिकों को भी बड़ा सबक है,जो पूर्वाग्रही बने रहने के कारण निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। हालांकि सात में से पांच एग्जिट पोल ने जता दिया था कि असम और बंगाल में भाजपा इतिहास रचने जा रही है,सो रच भी दिया। लेकिन तमिलनाडु में परिणाम सटीक नहीं बैठे। एम के स्टालिन की द्रमुक को पोल साफ बहुमत दे रहे थे,जो सटीक नहीं बैठे। यहां हाल ही में अस्तित्व में आई अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कजगम 100 सीटों की जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। दूसरे नंबर पर एआईडीएमके-भाजपा गठबंधन है। अब यहां यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस गठबंधन के साथ बनती है। कांग्रेस चार सीटें जीत रही है, अतएव सरकार में उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ गठबंधन सरकार बना लेगा। पुंडुचेरी में भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। असम में भाजपा हिमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे,इसमें कोई संशय नहीं है।

पांचों प्रांतों में मतदाताओं ने जबरदस्त मतदान करके इतिहास रचकर साफ संदेश दिया था, कि बदलाव की जबरदस्त लहर देखने में आएगी। हिंदुस्तानियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता करते हुए असम में भाजपा की वापसी कर दी, वहीं घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछाने वाली ममता को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तमिलनाडु में यही सबक स्टालिन को मतदाताओं ने दिया है। स्टालिन को सनातनी हिंदुत्व को मलेरिया और डेंगू कहने में कभी कोई परहेज नहीं रहा। राजभाषा हिंदी के विरोध में भी वे हमेशा खड़े दिखाई देते रहे हैं। इस चुनाव के परिणामों ने संदेश दे दिया है कि अब हिंदी,हिंदुत्व और हिंदुओं का विरोध करने वाले दल और राजनेता,भारतीय राजनीति में चल नहीं पाएंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी के ऐसे ही आचरण के कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। ये नतीजे उन नेताओं के लिए भी सबक हैं,जो आतंकवाद और आतंकियों की पैरवी में ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई राष्ट्रभक्त की वकालात कर रहे हों।

बंगाल में तृणमूल की पराजय के बाद जैसे वामदल अपना वजूद खोते चले गए,वही हश्र ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल का देखने में आ सकता है ? दरअसल असम एवं बंगाल में सबसे बड़ा कोई मुद्दा रहा है तो वह घुसपैठ और इन राज्यों में बढ़ता इस्लामीकरण है। अनेक सीमांत जिलों में घुसपैठ ने दोनों राज्यों में जनसंख्यात्मक घनत्व को बिगाड़ दिया है। कई जिलों में मुस्लिमों की आबादी 90 से 95 फीसदी तक पहुंच गई है। इन बदतर हुए हालातों के प्रति नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मतदाताओं को जागरूक किया। हिंदू संदेशखाली और आरजीकर में हुए महिला दुष्कर्मों के चलते ध्रुवीकृत हुए। भाजपा ने इन मुद्दों को भुनाने की दृष्टि से आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार हुई डॉक्टर की मां रत्ना देबनाथ को पानीहाटी और संदेशखाली आंदोलन की चेहरा रहीं रेखा पात्र को हिंगलगंज से उम्मीदवार बनाया था। ये दोनों महिलाएं चुनाव में जीत के लिए बढ़त बनाए हुए हैं। इन महिलाओं की उम्मीदवारी से बंगाल की महिलाओं में संवेदना जगी और बदलाव की लहर बनाने में उनकी प्रमुख भागीदारी रही।

इन सब बिंदुओं ने बंगाल में लोकतंत्र की गरिमा को महिमामंडित करने का काम कर दिया। इसी का परिणाम रहा कि भाजपा को बंगाल में करीब 200 सीटें मिलने जा रही हैं। 15 साल राज करने वाली ममता को सौ सीटें भी नहीं मिल रही हैं। बंगाल में ऐसा 49 साल बाद संभव हो पाया कि निष्पक्ष मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग पूरी तरह चौकन्ना रहा। जहां से भी गड़बड़ी की खबर मिली, तुरंत एक्शन लिया। इस कारण लंबे समय तक अराजक तत्वों द्वारा मतदान रोकना संभव नहीं हो पाया। किसी भी झड़प को बड़े संघर्ष का रूप लेने से पहले ही केंद्रीय बलों के जवान उसे नियंत्रित करने में सफल दिखे। पहली बार अमल में लाई गई त्वरित प्रतिक्रिया (रिस्पांस) दल ने भी अपने दायित्व का पूर्ण रूप से पालन किया। बावजूद फालता में 21 मई को पुनर्मतदान होगा। यहां ईवीएम से छेड़छाड़ की गईं। बूथ कब्जा लिए। एक ईवीएम पर तो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर टेप चिपका मिला। यदि 2.40 लाख सैन्य बलों की तैनाती नहीं होती तो बंगाल में लोकतंत्र बुरी तरह प्रभावित होता। दरअसल बंगाल में इसके पहले हुए चुनावों में तृणमूल के कार्यकर्ता और अवैध घुसपैठिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंदुओं को मतदान नहीं करने देते थे। इस बार सेना की कठोरता के चलते हिंदुओं ने धुर्वीकृत होकर मतदान में भागीदारी की। इसलिए इस बार बंगाल में पिछली बार की तुलना में करीब 9 प्रतिषत अधिक वोट पड़े थे,जो भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुए। आयोग ने एसआईआर के जरिए भी घुसपैठ करके अवैध मतदाता बने करीब 92 लाख मतदाताओं को मत से वंचित कर दिया था। इनमें से बढ़ा प्रतिशत तृणमूल के समर्थकों का रहा है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि भाजपा आई तो बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मुस्तैद हो जाएगी।

बड़े मत प्रतिशत का सबसे अहम, सुखद व सकारात्मक पहलू है कि यह अनिवार्य मतदान की जरूरत की पूर्ति कर देता है। हालांकि फिलहाल हमारे देश में अनिवार्य मतदान की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। निकट भविष्य में इस उम्मीद की पूरी होने की संभावना भी नहीं है। मेरी सोच के मुताबिक ज्यादा मतदान की जो बड़ी खूबी है, वह है कि दल व उम्मीदवारों को अल्पसंख्यक व जतीय समूहों की वोट बैंक की लाचारगी से छुटकारा मिल जाता है। इससे कलांतर में राजनीतिक दलों को भी तुष्टिकरण की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। अतएव अगले चुनावों में हम देखेंगे कि क्षेत्र विषेश से जुड़े मतदाताओं की अहमियत लगभग खत्म हो जाएगी। नतीजतन उनका संख्याबल जीत या हार की गारंटी नहीं रह जाएगा। लिहाजा सांप्रदायिक व जातीय आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नगण्य हो जाएगी। एसआईआर के जरिए देश से घुसपैठिए बाहर कर दिए जाते हैं तो इस अवैध घुसपैठ से लाभ उठाने वाले नेताओं की भूमिका को भी जनता नकार देगी। जैसे कि असम और बंगाल में देखने में आने लगा है।

ट्रंप ने सिर्फ तेल देखा, तेल की धार नहीं देखी

कटाक्ष

डॉ. श्रीकांत द्विवेदी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

बुजुर्गों ने बहुत सोच-समझकर बहुजन उपयोगी 'तेल देखो, तेल की धार देखो' जैसी लोकोक्ति की शुरुआत की होगी। इस लोकोक्ति का आशय यही कि सबसे पहले परिस्थिति को समझें, उसका ठीक से आकलन करें और फिर विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करें। इससे होने वाले संभावित नुकसान से बचा जा सकता है। जो विवेकी होते हैं, वे समझदारी के साथ परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक आकलन करते हैं। फिर समय की जरूरत अनुसार अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। दूसरे वे होते हैं जो त्वरित में कदम उठाते हैं। परिस्थितियों और परिणाम को समझे बगैर ही काम की शुरुआत कर डालते हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। माना कि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। मगर, जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दूसरी श्रेणी के लोगों में आते हैं। इनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि इन्हें परिस्थितियों का जायजा लेना ही नहीं पड़ता है। जो बोल दिया सो बोल दिया। परिणाम की चिंता वे करें, जो सोचते हो। ज्यादा सोचने से ओवर कॉन्फिडेंस का मजा बिगड़ जाता है। बस, इसीलिए अपने भूरिया भाई भी बिना सोचे ही बयान दे देते हैं। बयान भी ऐसे कि आज कुछ, कल कुछ और परसों कह देंगे 'मैंने तो कुछ बोला ही नहीं।'

अब पहलगाम की आतंकी घटना एवं ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप दादा खुद अपनी पीठ ठोकने लगे। फटाफट बयान दे डाला कि मेरी मध्यस्थता की वजह से युद्ध समाप्त हुआ। अन्यथा लाखों लोग मारे जाते। जबकि, हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस युद्ध विराम में तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं रही। इस सफेद झूठ के बाद दो-तीन देशों के और युद्ध विराम का तमगा पहन शांति के लिए नोबल पुरस्कार पाने का मन बना लिया। वहां भी कुछ हाथ न लगा, तो दुनिया के अनेक देशों पर टैरिफ का खेल शुरू कर दिया। जो कभी कम, कभी ज्यादा। यहां भी कोई खास बात नहीं बनी तो अपनी बिना ब्रेक की गाड़ी ईरान की तरफ मोड़ दी। शुरुआत में धमकियां चलती रही। बात नहीं बनी तो फिर चालीस दिन तक तबाही का सिलसिला चलता रहा।

इस बीच जिनसे उम्मीद थी, वे साथ देने से पीछे हट गए। युद्ध के दौरान कभी शांतिदूत बनने की मंशा, कभी पाषाण युग की बात तो कभी सभ्यता मिटा देने की धमकी। इन हवाई बयानों से भी बात नहीं बनी तो स्वत- ही सीजफायर की घोषणा। वार्ता की तैयारी, वार्ता विफल। जो कि होना ही थी। पाकिस्तान की मध्यस्थता में शांति कभी संभव नहीं। वह तो मुनीर है, जो बीते बरस बिन बुलाए मेहमान की तरह व्हाइट हाउस में लंच कर आये थे।उस एक प्लेट लंच की कीमत चुकाना थी। सो पहले शांति के लिए नोबल पुरस्कार का प्रस्ताव, फिर युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पाकिस्तान को अगुआ होना पड़ा। नतीजा सिफर। अब होर्मुज पर नाकाबंदी की बात चल रही है ।

कुल मिलाकर कहने का आशय यही है कि इस चालीस दिनी युद्ध में ट्रंप ने केवल और केवल ईरान में तेल ही तेल देखा, ईरान के भीतर तेल की धार देखने की कोशिश नहीं की। बिना सिर-पैर के बयान और झूठ की बैसाखियों के सहारे दादागिरी आखिर कब तक। विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर अपने ही देश में लोकप्रियता की रेटिंग 36 प्रतिशत तक ही रह गई। सत्ता के मद से परे रहकर ट्रंप ने तेल के साथ तेल की धार भी देखी होती तो आज लोकप्रियता में इतनी गिरावट नहीं आती। बहरहाल फिल्म 'बॉबी' के एक गीत की पंक्तियां ट्रंप की वर्तमान छवि से कितनी मेच कर रही है। पंक्तियां यूं कि 'झूठ बोले कौवा काटे, भूरे कौवे से डरियो।'

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

पब्लिक बोली सिंहासन छोड़ो, अब खेला हम करीबो

गाँव की चौपाल से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक, हर जगह एक ही चर्चा है, क्या सोच कर वोट दिया था, और हो क्या गया। यही लोकतंत्र का सबसे रोचक और रहस्यमय पक्ष है। चुनाव से पहले जनता बड़े-बड़े सपने बुनती है। सड़कें चमकेंगी, रोजगार की बारिश होगी, महँगाई गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मतदान संपन्न होता है, एक अजीब-सी शांति छा जाती है, मानो जनता खुद ही कह रही हो। अब पाँच साल की छुट्टी।

व्यंग्य

प्रभुनाथ शुक्ल

लेखक पत्रकार हैं।

पाँच राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आते ही देश की जनता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि असली सत्ता उसी के हाथ में है। लोकतंत्र की असली मदारी वहीं है। बाद में वह खुद तमाशा बन जाय यह दीगर बात है। उससे भी बड़ी बात यह कि उसका मूड किसी मौसम से कम नहीं। कब बदल जाए, किस दिशा में मुड़ जाए, इसका अनुमान लगाना तो दूर, खुद जनता को भी पहले से नहीं पता होता।

गाँव की चौपाल से लेकर शहर की चाय की दुकानों तक, हर जगह एक ही चर्चा है, क्या सोच कर वोट दिया था, और हो क्या गया। यही लोकतंत्र का सबसे रोचक और रहस्यमय पक्ष है। चुनाव से पहले जनता बड़े-बड़े सपने बुनती है। सड़कें चमकेंगी, रोजगार की बारिश होगी, महँगाई गायब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मतदान संपन्न होता है, एक अजीब-सी शांति छा जाती है, मानो जनता खुद ही कह रही हो। अब पाँच साल की छुट्टी।

इस बार का चुनावी मिजाज कुछ ऐसा रहा जैसे बरसात का मौसम, कभी तेज धूप, कभी घने बादल, तो कभी मूसलाधार बारिश। नेता लोग पूरी कोशिश में लगे रहे कि हवा का रुख समझ लें, लेकिन असली हवा तो जनता के मन में बहती है। और यह मन कब करवट ले ले, इसका पूर्वानुमान किसी मौसम विभाग के पास भी नहीं।

लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। यहाँ राजा कोई जन्म से नहीं होता, जनता उसे बनाती है। और वही जनता, जब मन भर जाता है, तो बड़े आराम से कह देती है अब बहुत हुआ, नीचे उतरिए। मतदान केंद्र पर उँगली पर स्याही लगते ही हर नागरिक के भीतर एक अदृश्य सत्ता जाग उठती है। वह खुद को देश का निर्णायक मानने लगता है। वोट डालकर बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े निर्णयकर्ता से कम नहीं होता।

राजनीति भी कम दिलचस्प खेल नहीं है। चुनाव के समय हर गली-नुक्कड़ पर मीठी बातें, वादों की मिठाई और भविष्य के रंगीन सपनों की सजावट होती है। हर भाषण में उम्मीद की नई इमारत खड़ी की जाती है। लेकिन जैसे ही परिणाम आते हैं, जनता के मन में एक पुरानी घंटी बज उठती है, यह सब तो पहले भी सुना था!

धीरे-धीरे जनता भी परिपक्व हो रही है। अब वह सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं होती। अब वह सवाल पूछती है–क्या बदला? कैसे बदला? हमारे जीवन में क्या फर्क आया? यह प्रश्न अब आम बातचीत का हिस्सा बन चुके हैं। यह बदलाव लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जागरूक जनता ही असली ताकत होती है।

लेकिन व्यंग्य का सबसे रोचक पहलू यह है कि जनता खुद भी कभी-कभी भूल जाती है। आज जिस पर नाराज होती है, कल उसी से फिर उम्मीदें बाँध लेती है। राजनीति का यह चक्र ऐसा है जिसमें हर पाँच साल में नए चेहरे, नए संवाद और नई परिस्थितियाँ सामने आती हैं, लेकिन कहानी का मूल ढाँचा लगभग वही रहता है। लोकतंत्र दरअसल एक विशाल रंगमंच है। इसमें जनता निर्देशक है, नेता अभिनेता हैं और चुनाव सबसे बड़ा मंचन। दिलचस्प बात यह है कि दर्शक भी वही जनता है, जो कभी ताली बजाती है, कभी हूटिंग करती है और कभी पूरी पटकथा ही बदल देती है।

अब सबकी नजर अगले शो पर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगली बार जनता कौन-सा नया मोड़ लेकर आती है। क्योंकि इस पूरे खेल का एक ही अटूट नियम है जनता का मन। और सच यही है कि इस मन को समझ पाना शायद भगवान के लिए भी आसान नहीं।

स्मृतियां

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी हैं। वर्तमान में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफेसर हैं।

ऋतु सौन्दर्य से परिपूर्ण जीवन की मौलिक परिभाषा

माँ का स्थान इन सबमें, सबसे अलग, उत्कृष्ट और अपरिमेय होता है क्योंकि वह तो दया, करुणा, प्रेम, त्याग व संस्कार की प्रतिमूर्ति महसूस होती है। वह अपने पूरे जीवन में कभी कोई अपेक्षा किए बगैर अपने बच्चों के उज्ज्वल जीवन की कामना करती है। मेरी माँ प्रेमा त्रिपाठी का जीवन कुछ इसी प्रकार का था। 5 फ़रवरी, 2021 को, जब दूसरी बार कोविड की लहर आई तो वह हमसे बिछुड़ गई। उस दौरान हज़ारों लोगों ने अपने परिजनों को खोया। उन अभागों में एक मेरा व मेरे परिवार का भी नाम है। वैसी त्रासदी हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे।

जीवन एक ऋतु है। एक जीवन जीते हुए कितने उतार-चढ़ाव आते हैं। शायद ऋतुओं के भीतर भी कई उतार-चढ़ाव आते हैं।

इसीलिए जीवन और ऋतु कभी कभी एक से लगने लगते हैं। संबंधों, रिश्ते-नातों को तो ईश्वर बनाता है। हम सब केवल उन संबंधों को अच्छे से जी सकते हैं, बस। इन रिश्तों में भी माँ-पिताश्री का रिश्ता किसी भी जीवन के लिए पुरस्कार होता है। ये वे रिश्ते हैं जो अपने कई वसंत को काटकर निःस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को, पीढ़ियों को, खिलखिलाते हुए देखने के आदी होते हैं।

माँ का स्थान इन सबमें, सबसे अलग, उत्कृष्ट और अपरिमेय होता है क्योंकि वह तो दया, करुणा, प्रेम, त्याग व संस्कार की प्रतिमूर्ति महसूस होती है। वह अपने पूरे जीवन में कभी कोई अपेक्षा किए बगैर अपने बच्चों के उज्ज्वल जीवन की कामना करती है। मेरी माँ प्रेमा त्रिपाठी का जीवन कुछ इसी प्रकार का था। 5 फ़रवरी, 2021 को, जब दूसरी बार कोविड की लहर आई तो वह हमसे बिछुड़ गईं। उस दौरान हज़ारों लोगों ने अपने परिजनों को खोया। उन अभागों में एक मेरा व मेरे परिवार का भी नाम है। वैसी त्रासदी हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे।

पाँच वर्ष बीत गए। समय जाते देरी नहीं लगती। अपने जब बिछड़ते हैं तो लगता है जैसे ये कल की ही बात है। अभी भी घर में माँ की दस्तक जैसे रहती है। ऐसा लगता है कभी कहीं से निकलकर अभी आ जाएँगी। अभी कहीं से कुछ बोल देंगी। यहीं आकर पास में बैठ जाएँगी। पर अगले पल यही लगता है कि यह सब केवल हमारे मन के भ्रम थे। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? जो चला जाता है वह तो केवल हमारे मस्तिष्क में ही जीवित रहता है।

माँ ने ही समय का अब एहसास करा दिया है। जब थीं, हर समय उनका पास होना ही सुखद था। अब जब वह सशरीर हमारे बीच नहीं हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ खो सा गया है। यह खालीपन तभी समझ आता है जब व्यक्ति हमारे सन्निकट नहीं होता है। जब होता है तो हम उसको महत्व नहीं देते। अब माँ की अनुपस्थिति यह एहसास देती है कि काश! वह मुझे कुछ पल के लिए मिल जातीं। कुछ हम उनसे बात कर पाते। कुछ वह अपनी कहतीं, कुछ मैं उनसे पूछता। लेकिन यह सब एक असंभव क्रिया है। एक अमूर्त की मूर्त कल्पना में आख़िर मैं क्यों जीता हूँ, पता नहीं। लेकिन इसमें भी मेरी आत्मा उन्हें ढूँढते नहीं थकती। यह अतृप्ति ही माँ से मिलने की एक वजह संभवतः बने, जिसे मैं सदैव ठीक मानता हूँ।

आज़ जो हमें प्राप्त है, हम अपने वैभव में भी अभाव माँ-पिताश्री की अनुपस्थिति को समझते हैं। हर कोने में उनकी उपस्थिति हमारे आह्लाद, उत्साह, ऊर्जा को बढ़ाते थे। लेकिन यह जीवन ही है जो ऋतुओं की भाँति है। टिकता नहीं। चलायमान है। इसीलिए इसे सांसारिक व मायामोह के रूप में व्याख्या करते रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समय काल के साथ ऋतुओं की उपस्थिति होती है पर ऋतुएँ भी कहाँ बनी रहती हैं वे अपने आने वालों के लिए छोड़ देती हैं रिक्त स्थान और फिर नई ऋतु अपने होने का एहसास देती हैं। यह अजीब सा जीवन का फ़लसफ़ा है जिसे समझ पाना शायद हमारे बस में नहीं होता। इसीलिए हमारे जीवन के अनुभवी यह कहते हैं, वर्तमान को कभी अवॉयड न करो। उसे महत्व दो। वर्तमान के रिश्तों को कहते दो। जो रिश्तों से विछुड़ जाते हैं वे कभी फिर एक होने के लिए कितने जन्म संघर्ष करते हैं। माँ-पिता के रिश्ते को तो कदापि अपने वर्तमान के साथ खूब जीने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि वे अनमोल हैं।

यह जो हर परिस्थितियों में ढलकर जीने की कला है, कम लोगों में होती है। माँ के भीतर एक बहुत अच्छी कला थी की वह ऐसी ही थीं। हर माहौल में खुद को अनुकूल बनाकर जीने की कला उनमें थी।

भारत की महान नारियों का इतिहास उनके अपने इन्हीं गुणों से भरा हुआ है। माँ ने कोई युद्ध नहीं लड़ा और न ही वह स्वतंत्रता सेनानी थीं लेकिन भारत की यह विशेषता है कि वह अपनी स्त्री-शक्ति के सभी जीवन को समान महत्व देता है। इसलिए भी भारतीय इतिहास मेरी माँ के जीवन को विस्मृत करके अधूरा है। शायद भारत की किसी भी नारी-शक्ति को विस्मृत करने की उसमें शक्ति नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता।

माँ की पुण्य तिथि पर एक बार उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज यह कहने की स्थिति में हैं कि जिन्हें अपने गाँव, अपनी माटी, अपने देश और अपने लोगों से लगाव था। जिनके जीवन में ऋतुओं सा सौंदर्य था। जिनके जीवन से अनेक महिलाओं ने बहुत कुछ सीखा और उन्हें आज भी स्मरण रखते हैं यह उनके अपने जीवन के मूल्य थे, शायद इसलिए वह सबमें स्मरणीय हैं।

आज हम जब हम माँ के जीवन को मुड़कर देखते हैं तो यही प्रतीत होता है कि उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को हम देखें तो पता चलता है कि उनके जीवन से ऋतु जीवन सौन्दर्य की मौलिक परिभाषा हमें मिलती है जो आने वाले समय में भी हमारी नारी शक्ति को प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

संवेदनाओं का प्रदर्शन

मनीषा मंजरी

लेखक साहित्यकार हैं।

जब दर्द भी 'कंटेंट' बन जाता है...

सोशल मीडिया पर उस घटना से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो को बार-बार साझा किया जाने लगा। उन पर कविताएँ लिखी गईं, भावुक पंक्तियाँ जोड़ी गईं, और उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो वे किसी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम हों। एक माँ और उसके बच्चे की तस्वीर, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उसे भी बार-बार साझा किया गया। हर बार उसके साथ नए शब्द, नई भावनाएँ, और नई प्रतिक्रियाएँ जुड़ती गईं। यह दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के सामने खड़ा करता है, क्या यही हमारी संवेदनशीलता है? संवेदना का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम किसी का दुख देखकर भावुक हो जाएँ या आँसू बहाएँ। संवेदना का वास्तविक अर्थ है, किसी के दर्द की गरिमा को समझना और उसका सम्मान करना। हर पीड़ा को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, और हर भावना को सार्वजनिक करना भी आवश्यक नहीं होता। जब हम किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर को अपनी कविता या पोस्ट का आधार बनाते हैं, तो हम केवल एक कहानी नहीं लिख रहे होते। हम किसी की निजी त्रासदी को सार्वजनिक कर रहे होते हैं। उस तस्वीर के पीछे एक परिवार होता है, जिनके लिए वह केवल एक छवि नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया होती है।

हाल के दिनों में एक दर्दनाक घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। जबलपुर के बरगी डैम में बीस साल पुराने क्रूज के डूबने से कुछ ही पलों में कई जिंदगियाँ खत्म हो गईं, कई परिवारों के सपने बिखर गए, और कुछ रिश्ते हमेशा के लिए अधूरे रह गए। ऐसी घटनाएँ केवल समाचार नहीं होतीं, वे उन लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, जिनके लिए यह क्षति अपूरणीय होती है। लेकिन इस त्रासदी के बाद जो एक और दृश्य सामने आया, उसने मन को और भी अधिक विचलित कर दिया। सोशल मीडिया पर उस घटना से जुड़ी तस्वीरों और वीडियो को बार-बार साझा किया जाने लगा। उन पर कविताएँ लिखी गईं, भावुक पंक्तियाँ जोड़ी गईं, और उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया गया मानो वे किसी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम हों। एक माँ और उसके बच्चे की तस्वीर, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उसे भी बार-बार साझा किया गया। हर बार उसके साथ नए शब्द, नई भावनाएँ, और नई प्रतिक्रियाएँ जुड़ती गईं। यह दृश्य हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न के सामने खड़ा करता है, क्या यही हमारी संवेदनशीलता है?

संवेदना का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम किसी का दुख देखकर भावुक हो जाएँ या आँसू बहाएँ। संवेदना का वास्तविक अर्थ है, किसी के दर्द की गरिमा को समझना और उसका सम्मान करना। हर पीड़ा को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, और हर भावना को सार्वजनिक करना भी आवश्यक नहीं होता। जब हम किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर को अपनी कविता या पोस्ट का आधार बनाते हैं, तो हम केवल एक कहानी नहीं लिख रहे होते। हम किसी की निजी त्रासदी को सार्वजनिक कर रहे होते हैं। उस तस्वीर के पीछे एक परिवार होता है, जिनके लिए वह केवल एक छवि नहीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया होती है।

क्या हमने कभी यह सोचा है कि जब वे लोग इन तस्वीरों को बार-बार सोशल मीडिया पर देखते होंगे, तो उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? क्या यह उनके घावों को भरने में मदद करता है, या उन्हें और गहरा कर देता है? आज के डिजिटल युग में अभिव्यक्ति के साधन बहुत आसान हो गए हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी बात कहने का मंच है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि इससे विचारों का आदान-प्रदान संभव हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक नई आदत भी विकसित हुई है, हर अनुभव, हर भावना और हर घटना को तुरंत साझा करने की। हम अपने जीवन के हर छोटे-बड़े क्षण को इस तरह प्रस्तुत करने लगे हैं कि वह दूसरों के लिए भी दृश्य बन सके। धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हम दूसरों की पीड़ा और कठिन परिस्थितियों को भी उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। यहाँ समस्या केवल साझा करने की नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण की है, जिससे हम इन घटनाओं को देखते हैं।

जब किसी त्रासदी को हम एक 'कहानी' या 'कंटेंट' के रूप में देखने लगते हैं, तो हम उसकी वास्तविकता और उसकी गंभीरता को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। संवेदनाएँ जितनी गहरी होती हैं, उतनी ही शांत होती हैं। उन्हें शोर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि समझ और सम्मान की आवश्यकता होती है। कभी-कभी मौन ही सबसे सशक्त अभिव्यक्ति होता है। मौन का अर्थ यह नहीं है कि हम उदासीन हैं या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उस पीड़ा को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उसे शब्दों में बाँधने की आवश्यकता महसूस नहीं करते।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी अभिव्यक्ति के साथ-साथ अपनी संवेदनशीलता की भी रक्षा करें। हमें यह समझना होगा कि कब बोलना आवश्यक है और कब चुप रहना अधिक उचित है। आत्ममंथन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम जो साझा कर रहे हैं, वह वास्तव में सहानुभूति से प्रेरित है, या केवल एक आदत बन चुका है? क्या हमारी अभिव्यक्ति किसी की पीड़ा को कम कर रही है, या उसे और अधिक सार्वजनिक बना रही है?

यह भी समझना आवश्यक है कि हर भावना को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची संवेदना को किसी दर्शक या प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। वह भीतर से उत्पन्न होती है और वहीं अपनी पूर्णता प्राप्त करती है। समाज की संवेदनशीलता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि हम कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितनी गहराई से समझते हैं। शायद अब समय आ गया है कि हम यह सीखें, दर्द को महसूस करें, पर उसे प्रदर्शन में बदलने से बचाएँ। क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं, जिन्हें शब्दों में नहीं, बल्कि खामोशी में ही सम्मान दिया जा सकता है।

रचना समय

आशीष दशोत्तर

टिप्पणीकार साहित्यकार हैं।

कम होते स्पेस में विचार की तरह फैलती कविताएं

ठीक इसी तरह कविता के लिए चाहे स्पेस न हो , वह अपना हिस्सा ले ही लेती है। ब्रज भाई की कविताओं को 'रचना समय' की श्रृंखला के तहत प्रकाशित कर संपादक हरि भटनागर और बृज नारायण शर्मा ने समय से सवाल करती कविताओं को स्थान दिया है। इस पुस्तक की कविताएं बहुत ख़ामोशी के साथ पाठक को वहां ले जाती है , जहां उसे पहुंचना चाहिए। ये कविताएं बड़े नारे नहीं लगातीं लेकिन उंगली पड़कर उस भाषा के बीच ले जाती है, जहां मनुष्यता आज भी ज़िंदा है। किसी मोहल्ले के लोकतंत्र से लेकर किसी घर के किचन में स्त्रियों के बीच लोकतंत्र की बात करते हुए ब्रज श्रीवास्तव पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लग रहे प्रश्नों को इशारों ही इशारों में उठाते हैं।

निरंतर बढ़ती जगहों के बीच कम हो रही है मनुष्यता के लिए जगह। कम हो रही है रचनात्मकता के लिए जगह। कम हो रही है सभ्यता के लिए जगह। कम हो रही है कविता के लिए जगह। इस कम होती जगह में कविता का संसार रच रहे कवि ब्रज श्रीवास्तव की कविताएं एक विचार की तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं।

ब्रज श्रीवास्तव की कविताएं बहुत क़रीब से गुज़रती हुई कविताएं हैं। इन कविताओं के भीतर वह स्पेस मौजूद है जिसकी तलाश आज मनुष्यता को है। यह समय कविता का नहीं है। इस समय कविता को दरकिनार किया जा रहा है। एक ऐसा आभामंडल तैयार किया जा रहा है, जिसमें रचनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। जहां सृजनात्मकता के लिए समय अनुपलब्ध है। ऐसे समय में ब्रज श्रीवास्तव कहते हैं -

समय को स्थान मैं नहीं दूंगा
तो भी वह ले ही लेगा
अपना हिस्सा इस धरती पर।

ठीक इसी तरह कविता के लिए चाहे स्पेस न हो, वह अपना हिस्सा ले ही लेती है। ब्रज भाई की कविताओं को 'रचना समय' की श्रृंखला के तहत प्रकाशित कर संपादक हरि भटनागर और बृज नारायण शर्मा ने समय से सवाल करती कविताओं को स्थान दिया है। इस पुस्तक की कविताएं बहुत ख़ामोशी के साथ पाठक को वहां ले जाती है, जहां उसे पहुंचना चाहिए। ये कविताएं बड़े नारे नहीं लगातीं लेकिन उंगली पड़कर उस भाषा के बीच ले जाती है, जहां मनुष्यता आज भी ज़िंदा है। किसी मोहल्ले के लोकतंत्र से लेकर किसी घर के किचन में स्त्रियों के बीच लोकतंत्र की बात करते हुए ब्रज श्रीवास्तव पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लग रहे प्रश्नों को इशारों ही

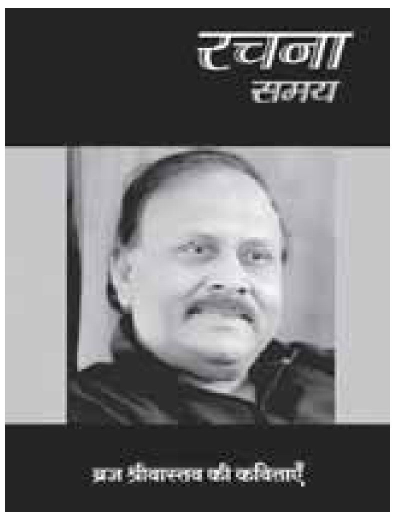

इशारों में उठाते हैं। एक कविता में वे कहते हैं -

सबसे पहले शोषित ने विरोध किया
फिर कवि ने विरोध किया
फिर विरोध एक नीति बनी
फिर लोकतंत्र बना और लोकतंत्र में हमने
अपने-अपने सच के प्रकाश में
एक लोक सच पाया।
सभी को विरोध मिला
पर विरोध से जिसने रखा गिला उसे क्रोध आया,
क्रोध से क्रोध मिला तो युद्ध हुआ
इस तरह वातावरण अशुद्ध हुआ।
यदि विरोध के बिंदुओं पर विचार हो
तो यह माहौल धीरे-धीरे लोकतांत्रिक हो
खुशगवार हो,
जैसा मनुष्य को चाहिए वैसा संसार हो।

दुर्भाग्य से आज मनुष्य को उसका वही संसार नहीं मिल रहा है। ब्रज भाई अपनी कविता में उसी मनुष्य के क़रीब जाकर उसकी धड़कन को सुनने का प्रयास करते हैं। उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने की कोशिश करते हैं। उसके दिल में उठ रहे सवालों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं।

इस संग्रह की कविताएं एम्बुलेंस, पुकार नहीं पा रहा हूं, हम गवाह हैं, मैं ही वंचित रहा, युद्ध, दुनिया का बदन आज की विपरीत परिस्थितियों के बीच बची हुई उम्मीद को सहेज रही हैं। इन कविताओं पर संपादकद्वय की टिप्पणी तो मानीखेज है ही, साथ ही वरिष्ठ कवि, समीक्षक विजय कुमार, लीलाधर मंडलोई, प्रियदर्शन और बोधिसत्व की टिप्पणियां ब्रज भाई की कविताओं के सार्थक होने की ताईद करती हैं। इन टिप्पणियों को पढ़कर ब्रज श्रीवास्तव की कविताओं के भीतर बह रही धारा को बखूबी समझा जा सकता है। रचना समय के ज़रिए सामने आई ये कविताएं बहुत आगे जानी चाहिए और रचना समय के माध्यम से ऐसे ही कविताओं को आगे लाने का प्रयास निरंतर होना चाहिए।

रचना समयःब्रज श्रीवास्तव की कविताएं
संपादक - हरि भटनागर, बृज नारायण शर्मा
प्रकाशक - रचना समय, भोपाल
मूल्य - 100/-

सचिन शर्मा के रूप में धार को मिला नया कप्तान, पहले ही दिन एक्शन मोड में नजर आए एसपी

सख्त कार्यशैली के लिए मशहूर पुलिस कप्तान से बहुत आशाएं हैं धार जिले को

धार से राजेश शर्मा

एसपी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले धार जिले के पुलिस कप्तान सचिन शर्मा के बारे में प्रशासनिक गलियारों से लेकर हर और एक ही चर्चा है कि वे अपनी सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। क्विक एक्शन से लेकर कड़ी कार्रवाई...।

भौगोलिक रूप से प्रदेश के बड़े जिले और विविधताओं के लिए धार जाना जाता है ऐसे में सचिन शर्मा की कार्यशैली आशा की किरण के रूप में देखी जानी चाहिए। बीते कुछ समय में घटित हादसों और दुर्घटनाओं ने इस संभावनाशील जिले के माथे पर कई बदनुमा दाग लगाए हैं। ऐसे में यह जिला और यहां के बाशिंदे एक सख्त प्रशासक की बाट जोह रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर बहुत आशाएं हैं धार जिले को नवागत एसपी सचिन शर्मा से।

धार जिले की कमान संभालते ही नवागत पुलिस कप्तान सचिन शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी प्राथमिकता जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और अपराधी तत्वों पर नकेल कसना है। 2014 बैच के आईपीएस

सचिन शर्मा के लिए धार नया नहीं है, वे 2018 में एडिशनल एसपी के रूप में धार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

दिल्ली से पढ़ाई, लॉ में डिग्री और 5 जिलों का अनुभव..– पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसपी शर्मा ने अपना परिचय दिया। मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले सचिन शर्मा की शिक्षा दिल्ली में हुई है और उनके पास कानून की डिग्री है। धार आने से पहले वे उज्जैन, छतरपुर और उमरिया जैसे चुनौतीपूर्ण जिलों में एसपी रह चुके हैं। उनका प्रोबेशन ग्वालियर में और सीएसपी के रूप में कार्यकाल उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में रहा है।

धार मेरे लिए घर जैसा है यहाँ की भौगोलिक स्थिति और चुनौतियों को मैं पहले से समझता हूँ , 'सुरक्षित धार, समृद्ध धार' बनाना है

नवागत एसपी सचिन शर्मा ने पत्रकारों के सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच का संवाद टूटना नहीं चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन अब और अधिक पारदर्शी तरीके से काम करेगा। जिले में हो रही चोरी और लूट जैसी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। धार मेरे लिए घर जैसा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और चुनौतियों को मैं पहले से समझता हूँ। हमारी प्राथमिकता 'सुरक्षित धार, समृद्ध धार' बनाना है।

'डेथ जोन' बनेंगे 'सेफ जोन'

एसपी ने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय हैं। पुलिस ने ऐसे 'ब्लैक स्पॉट्स' की पहचान की है जहाँ बार-बार हादसे होते हैं। उन्होंने कहा, हमारा टारगेट जीरो टॉलरेंस है। सड़कों पर होने वाली मौतों के आंकड़े को शून्य पर लाने के लिए हम एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेंगे।

'पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग' पर जोर ताकि आम आदमी बिना डरे पुलिस के पास आ सके

कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावी गश्त (पैट्रोलिंग) सख्त चेकिंग के जरिए अपराधियों में डर पैदा किया जाएगा। उन्होंने 'पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग' पर जोर दिया ताकि आम आदमी बिना डरे पुलिस के पास आ सके।

शहर का ट्रैफिक : मास्टर प्लान से सुधरेगी व्यवस्था

धार शहर में फुटपाथ की कमी और सड़कों पर बढ़ते दबाव को लेकर पूछे गए सवालों पर एसपी ने स्वीकार किया कि यातायात व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, हम नगरपालिका के साथ समन्वय बिठाकर अतिक्रमण हटाएंगे और दुकानदारों से बात कर आदर्श सड़क पर यातायात को सुचारू बनाएंगे।

अधिसूचना तक सीमित कालोनियों को वैध करने की प्रक्रिया

शहर की 93 अनाधिकृत कालोनियों का विकास अटका

बैतूल। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया केवल अधिसूचना जारी करने तक सिमट कर रह गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद कुछ कॉलोनाइजरों को नोटिस दिए गए, इसके बाद आज तक न तो किसी भी कॉलोनी का विकास शुल्क जमा हुआ और न ही वसूल करने की पहल हो सकी। परिणाम स्वरूप अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेने और मकान बनाने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। दरअसल वर्ष 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई इन कॉलोनियों को वैधता और विकास देने के लिए शासन ने 16 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी की थी। करोड़ों रुपए की योजनाएं भी बनी, सर्वे हुए, नक्शे तैयार हुए, लेकिन जमीन पर विकास का एक भी बड़ा काम शुरू नहीं हो सका। इन कॉलोनियों में सड़क़ बिजली, पानी और अन्य नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए 106 करोड़ 64 लाख 81 हजार रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया है। नियमानुसार यह राशि संबंधित कॉलोनाइजरों से वसूली जानी थी, लेकिन अधिकांश कॉलोनाइजर या तो शहर छोड़ चुके हैं, कई की मृत्यु हो चुकी है और कुछ के परिजनों ने भुगतान से हाथ खड़े कर दिए हैं। नतीजतन पूरी व्यवस्था प्रशासनिक असमंजस में फंस गई है।

शहर में मिली थी 93 कॉलोनियां- प्रशासन और नगरपालिका द्वारा किए गए सर्वे में 31 दिसंबर 2016 के पहले अस्तित्व में आई 93 कॉलोनियां मिली थी। इस पर प्रशासन ने मध्यप्रदेश पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत 16 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद कुछ को नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इसके आगे बात नहीं बढ़ सकी। नतीजतन, इन कॉलोनियों को आज भी वैध नहीं किया जा सका है। इन कॉलोनियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अनुमानित राशि 106 करोड़ रुपये से अधिक की आंकी गई थी। यह राशि कॉलोनाइजरों और उनके न होने पर, कॉलोनियों के प्लॉट-मकान मालिकों से वसूल की जानी थी। लेकिन राशि वसूली को लेकर किसी ने भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे इसके बाद कुछ भी नहीं हो सका।

किस क्षेत्र में कितनी अवैध कालोनियां- शहर में 93 अनाधिकृत कॉलोनियां है। इनमें अवैध कॉलोनियों में सबसे ज्यादा 34 कॉलोनियां टिकारी की है। इनके अलावा हमलापुर में 18, खंजनपुर में 15, बदनूरढाना में 14, गौठाना में 11 और खकरा जामठी में 1 अवैध कॉलोनी है। इनमें से पार्क के लिए महज 1 कॉलोनी में जगह है, वहीं 2 कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां पर प्लॉट बेचने के बाद कोई जमीन ही नहीं बची है। अधिकांश में नाम के लिए जगह तो बची है, लेकिन इतनी नहीं कि उन्हें बेच कर राशि वसूल की जा सके या और कोई उपयोग किया जा सके। अनाधिकृत कॉलोनी होने के कारण कई खाली भूखंडों पर भवन निर्माण अनुमति भी नहीं मिल रही। यानी जिन लोगों ने जमीन खरीदी, वे न घर बना पा रहे और न ही उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल रही है।

कॉलोनियों में होना हैं विकास कार्य- आंकड़े बताते हैं कि 93 कॉलोनियों का कुल भू-क्षेत्र बेहद विशाल है। इतने बड़े भू-क्षेत्र और संसाधनों के बावजूद नागरिक सुविधाओं का अभाव कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जिन कॉलोनियों में पार्क और सार्वजनिक उपयोग की जमीन होनी चाहिए थी, वहां अधिकांश स्थानों पर जमीन बची ही नहीं। आरोप हैं कि पूर्व में कॉलोनाइजरों ने पार्क की भूमि तक बेच दी। नतीजा यह है कि बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के बैठने और सामुदायिक गतिविधियों के लिए खुली जगह उपलब्ध नहीं है। इधर अवैध कालोनियों होने की वजह से यहां रहने वाले लोगों को बिजली, पानी, सड़क़ जैसी बुनियादी सुविधाएं भी यहां मुहैया नहीं हो पाती। ऐसी कॉलोनियों में जरुरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन कॉलोनियों का विकास करने की पहल की गई थी। इसके तहत बाकायदा सर्वे कराया गया था और यह आंकलन भी किया गया था कि इन कॉलोनियों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने कितनी राशि खर्च करना होगा। लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है।

वसूली को लेकर शुरू नहीं हुई कार्रवाई

प्रशासन अब दो विकल्पों पर विचार कर रहा है पहला, कॉलोनियों में बची खाली जमीन की नीलामी कर राशि जुटाना और दूसरा, रहवासियों से प्रति वर्गमीटर के हिसाब से विकास शुल्क वसूलना, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दोनों विकल्पों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हुई। कुछ नोटिस जारी कर दिए गए, मगर वसूली और विकास की दिशा में कोई प्रभावी कदम सामने नहीं आया। यहीं वजह है कि इन कालोनियों में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कई कॉलोनियों में आज भी कच्ची सड़कें हैं, नालियां अधूरी है, गर्मियों में पानी संकट है और बरसात में कीचड़ से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई जगह बिजली व्यवस्था भी अस्थायी इंतजामों पर निर्भर है।

इनका कहना है –

मुझे अभी इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं है। जल्द ही पूरी जानकारी लेकर इस दिशा में कार्य किया जायेगा।

– नवनीत पाण्डेय,
सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

साहित्यकार पार्क में भवन का भूमिपूजन आज

भोपाल। भोपाल कलामन्दिर संस्था की पहल पर भोपाल शहर को प्रदेश के पहले साहित्यकार पार्क में भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन कल प्रातः दिनांक 6 मई को प्रातः 10.30 बजे। बड़े ही हर्ष का प्रसंग है कि कलामन्दिर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि संस्था की माँग पर महापौर मालती राय जी ने वार्ड नं 31 प्लेटिनम प्लाज़ा के सामने नवदुर्गा खाटूश्याम मन्दिर के सामने के पार्क को कलामन्दिर साहित्यकार पार्क के नाम पर आवंटित किया, जिसमें विधायक श्री भगवानदास सबनानी ने अपनी विधायक निधि से राशि आवंटित कर मध्यप्रदेश शासन से पार्क में एक दो मंजिल भवन निर्माण की अनुज्ञा स्वीकृत करवा दी है। यह कार्य शीघ्रता से सम्पन्न हो अतः पंडित विष्णु राजोरिया जी के कल दिनांक 6 मई 2026 को प्रातः 10.30 बजे भूमि पूजन का मुहूर्त बताया है। कार्यक्रम में भोपाल नगर के सांसद श्री आलोक शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, पंडित डॉ. विष्णु राजौरिया वार्ड पार्षद श्रीमती ब्रजुला सचान, एवं कलामन्दिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ गौरीशंकर शर्मा 'गौरीश' सहित कलामन्दिर संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारी / सदस्य एवं शहर की साहित्यिक संस्थाओं के सभी साहित्यकार उपस्थित रहेंगे।

श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, एक की मौत

पूजा कर लौट रहे थे 35 लोग, 25 घायल, तेज रफ्तार में मोड़ पर हुई अनियंत्रित

बैतूल। मोहदा थाना क्षेत्र में देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। ट्रॉली में करीब 35 महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सवार थे। सभी लोग गुप्तवाड़ा में पूजा-अर्चना कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। घटना सोमवार रात करीब 8 बजे खेरा-कुनखेरी हनुमान मंदिर के पास हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तेज मोड़ पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 और मोहदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। डायल 112 के पायलट गोविंद बिल्लोरे, प्रधान आरक्षक सचिन माहोरे और एसआई रामस्वरूप रघुवंशी ने घायलों को तत्काल भीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। कुछ घायलों को निजी वाहनों की मदद से भी अस्पताल ले जाया गया। रात 2 बजे तक 13 गंभीर घायलों को बैतूल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बैतूल जिला अस्पताल में घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने बताया कि हादसे में भोडिलावा निवासी 90 वर्षीय बुकला की मौत हुई है। मृतक का पोस्टमार्ट्म भीमपुर में कराया गया। अन्य घायलों का इलाज भीमपुर में किया जा रहा है।

हादसे में ये लोग हुए घायल– ट्रेक्टर- ट्रॉली पलटने की घटना में करीब 25 लोग घायल हुए है। घायलों में भोडिलावा निवासी कृष्णा (14), रामबाई (50), कोटमी निवासी बीसराम (50) और गोलाई निवासी ईश्वर (24) घायल हुए हैं। इनके अलावा फुलवती (3), जयश्री (30), कली (30), अर्जुन (25), उर्मिला (30), रेखा (30), शिवराम (40), तुलसीराम (28) और लोधी (60) को भी चोटें आई हैं। किसी को फ्रैक्चर तो किसी को अंदरूनी चोटें लगी हैं।

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का करें त्वरित निराकरण : कलेक्टर

बैतूल। बैतूल कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं। इस दौरान कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में चिचोली निवासी अजय खुरसना ने निजी भूमि पर जबरन फसल नष्ट करने की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार चिचोली को पुलिस से समन्वय कर आवेदक की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।घोड़ाडोंगरी निवासी मालतीराव की सीमांकन संबंधी शिकायत का तहसीलदार घोड़ाडोंगरी को निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

खसरा रिकॉर्ड में सुधार किए जाने के निर्देश– जनसुनवाई में आमला तहसील के ग्राम बोडख़ी निवासी अल्पना बामने ने खसरा रिकॉर्ड में सुधार किए जाने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर ने भैंसदेही एसडीएम को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। मुलताई तहसील के ग्राम सूखाखेड़ी निवासी झनक सिंह ने आवेदन के माध्यम से भूमि का अवैध कब्जा हटाए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने मुलताई तहसीलदार को जांच कर आवेदक की समस्या का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

आवासीय पट्टा प्रदाय किए जाने

जनसुनवाई में हमलापुर निवासी जमुना विश्वकर्मा ने आवासीय पट्टा प्रदाय किए जाने के लिए जनसुनवाई में आवेदन दिया प्राप्त। आवेदन पर कलेक्टर ने एसडीएम बैतूल को जांच के निर्देश दिए। ग्राम कुंडई निवासी नकुल ने मरीज की गंभीर समस्या को देखते हुए सहायता राशि प्रदान किए जाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने सीएमएचओ और श्रम विभाग के अधिकारी को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। सोनाघाटी निवासी कमला पंडाग्रे ने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन न दिखने की शिकायत की। जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम शाहपुर को जांच कर आवेदक की समस्या का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। बैतूल निवासी रविंद्र चौकीकर ने अनावेदक के खेत से आने जाने का रास्ता दिलाने के लिए आवेदन किया। जिस पर कलेक्टर ने आमला तहसीलदार को मौका की जांच कर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

पश्चिम बंगाल की फतह पर निकाला विशाल जुलूस, मोदी,भारत माता की जय, वंदे मातरम् से गूंजा नगर

सोहागपुर। पश्चिम बंगाल की फतह, असम,पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में विशाल जूलूस भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों, पदाधिकारियों, कार्यकताओं ने निकाला। इस विशाल जुलूस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लहराते हुए निकले। इस विशाल जुलूस में मोदी जिन्दाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम् के उद्घोष से नगर गूंजता रहा। विशाल जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों मुख्य बाजार, बस स्टैंड, नगर विभिन्न वार्डों से होकर निकला। देशभक्ति के रंग में समाएं विशाल जुलूस में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों एवं बैंड-बाजों की धुन पर कार्यकर्ता झूमते नजर आए। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत देश की जनता के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्वास, विकास और सुशासन की नीतियों परिणाम है। यह जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि आम जनता की आकांक्षाओं, विश्वास और परिश्रम का परिणाम है।नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे समर्पण और ऊर्जा के साथ पार्टी की नीतियों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करके संगठन को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को झाल मुड़ी आदि खिलाकर पश्चिम बंगाल, असम पांडिचेरी की जीत पर खुशी जताई। उल्लेखनीय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव के समय वहां झाल मुड़ी खाकर एक ऐसा संदेश दिया जिससे पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ हो गया। पश्चिम बंगाल में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हासिल कर रही है।जो स्वर्गीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह के कुशल रणनीति का परिणाम है। इस पश्चिम बंगाल फतह से स्वर्गीय पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को जाता है। इससे पश्चिम बंगाल में भारतीय सांस्कृतिक की विरासत पुनः स्थापित होगी।यह जीत देश की एकता एवं अखंडता के आवश्यक थीं।

पचमढ़ी में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अमले को दस दिन बाद चलता है पता मृत बाघ का, लापरवाही

सोहागपुर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लचर मानीटिरिग विभाग पर अधिकारियों कमजोर पकड़ के कारण पूर्व पचमढ़ी के दुर्गम बीट पठार (कक्ष क्रमांक पीएफ 250) में एक वयस्क नर बाघ का शव जो करीबन पांच छै दिन पूर्व का मिलने से संम्पूर्ण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गस्ती दल एवं कर्मचारियों एवं अधिकारियों की अकर्मण्यता की इंगित करता एवं कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। ऐसा लगता है प्रदेश सरकार जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में करोड़ों रुपए खर्च करके बाघों की सुरक्षा व्यवस्था पर भारी-भरकम बजट एवं दल बल के लिए करता है।वह केवल वीवीआईपी के आवभगत में अपना समय व्यतीत करके अपने नंबर बढ़ाने में लगा रहता है ऐसा कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी? या यह कहा जाए कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्या अब बाघों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है? क्योंकि कुछ अरसे समय में बाघों की लगातार हो मौतों हो रही है।बार बार क्षेत्र संचालक एवं अधिकारियों द्वारा एक रखा रटाया शब्द कि बाघ की मौत स्वाभाविक है? तब क्यों नहीं ऐसे संवेदनशील मामले में किसी भी पत्रकारों को आमंत्रित किया जाता है। आखिर क्यों सूचना छिपाकर बाघों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ऐसी परम्परा हमेशा देखी जा रही है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अमले को दसों दिन तक शव का न मिलना सतपुडा टाइगर रिजर्व के जिला अधिकारियों की कमजोर पकड़ एवं लापरवाही की तरफ इंगित करता है। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एसडीओ आशीष खोबरागड़े को ऐसे संवेदनशील सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दो दो स्थानों पिपरिया एवं सोहागपुर के सतपुडा टाइगर रिजर्व मढ़ई का अतिरिक्त प्रभार विगत करीबन एक साल से दे रखा है। आखिर क्यों सतपुडा टाइगर रिजर्व की संचालक ने प्रदेश सरकार का ध्यानाकर्षण क्यों नहीं कराया यह बड़ा सवाल है । ऐसे मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को अभी तक हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ की मोतों पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर सुक्ष्म हर कड़ी पर ध्यान करके जांच करना आवश्यक है। तभी ऐसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ऐसे होने वाले हादसे पर अंकुश लगा सकता है।

ताज़ा स्थिति

मध्यप्रदेश में 2026 में ताजा स्थिति मई 2026 में तक कुल 28 बाघों की मौत हो चुकी है। इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी क्षेत्र (हांडी खोह की खाई) में हाल ही में एक बाघ का शव मिला है, जो करीब 10 दिन पुराना था। वहीं 2025 के आंकड़ों में साल 2025 में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 54 से 55 बाघों की मौत हुई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जहर देने, करंट लगने और आपसी संघर्ष के कारण बाघों की मौत के कई मामले सामने आए थे। अगस्त 2025 में भी रिजर्व में एक बाघ मृत पाया गया था। शिकार और जहर देनाः मार्च 2026 में सतपुड़ा रिजर्व की सीमा के पास एक बाघिन को जहर देकर मारने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

सुरक्षा के कदम

पता चला है कि बाघों की बढ़ती मौतों को देखते हुए प्रशासन ने टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स पीएंडटीः सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए एक विशेष बल का गठन किया गया है।जिसमें 24 युवाओं को पचमढ़ी में 'जंगल कमांडो' के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

संक्षिप्त समाचार

हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की द्वितीय परीक्षा 7 मई से

हरदा (निप्र)। प्रदेश में हाई स्कूल और हायर सेकंडरी की द्वितीय परीक्षा 7 मई से प्रारंभ हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी की द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के प्रवेश-पत्र MPONLINE के पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

जिले में जनगणना 2027 के तहत किया जा रहा मकान गणना कार्य

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के कुशल मार्गदर्शन में जिला स्तर से अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती वंदना जाट द्वारा जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकानों की गणना का कार्य पूरी कर्मठता से कराया जा हैं। अपर कलेक्टर श्रीमती जाट द्वारा की जा रही मॉनिटरिंग और फील्ड टीम के उत्साहवर्धन से मैदानी अमले में भी ऊर्जा और उत्साह का प्रवाह हुआ है। जिला योजना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि सुबह से प्रगणक अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में घूम घूमकर कार्य कर रहें हैं। पर्यवेक्षक अपने प्रगणक दल के साथ उनकों तकनीकी और मैदानी सहयोग के लिए उपस्थित हैं। विदित हो कि वर्तमान में 21 चार्ज के लगभग 2800 गणना ब्लॉकों के लिए करीब 2400 प्रगणकों द्वारा फील्ड में नजरी नक्शा तैयार करने एवं मकान नंबरिंग के उपरांत एचएलओ ऐप में मकानों की गणना संबंधी प्रविष्टियों का कार्य किया जा रहा है। लगभग 400 पर्यवेक्षकों द्वारा प्रगणकों के कार्य का सत्यापन करते हुए फील्ड स्तर पर आ रही समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। बैतूल जिले में जनगणना कार्य के लिए 21 चार्ज अधिकारी हैं, जिनमें लगभग 2800 गणना ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में से आज सायंकाल तक करीब 800 गणना ब्लॉकों में मकान गणना कार्य प्रारंभ कर डेटा पोर्टल पर सफलतापूर्वक सिंक किया जा चुका है।

जिले की सभी आंगनबाड़ियों में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम आयोजित

सीहोर (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जिले की सभी आंगनबाड़ियों में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर के गंज स्थित शासकीय स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रियांशी चौहान ने इस योजना के लाभ के बारे में सभी को जानकारी दी। इस अवसर पर बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में श्री अर्जुन राठौर जी, पर्यवेक्षक सुश्री शशि राठौर, श्री भूपेंद्र अहिरवार, श्री संतोष राठौर सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थीं।

गिट्टी और बोल्डर के अवैध परिवहन में संलिप्त 03 वाहनों को किया जप्त

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को खनिज विभाग बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन दौरा कर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। खनिज अमले द्वारा गौण खनिजों के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहनों पर कार्यवाही करते हुए उन वाहनों को जप्त कर समीपस्थ पुलिस थानों की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। उप संचालक खनिज प्रशासन एवं खनि निरीक्षक बैतूल द्वारा खनिज अमले के साथ बैतूल क्षेत्रांतर्गत ग्राम भोगीतेड़ा के पास से खनिज गिट्टी के ओवरलोड परिवहन में संलिप्त 01 वाहन डम्पर कमांक एमपी 09 एचजे 0684 एवं कोसमी अंडर ब्रिज के पास से खनिज बोल्डर के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन डम्पर क्रमांक आरजे 07 जीसी 7839 को जप्त कर पुलिस थाना गंज बैतूल की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। वहीं बैतूल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम झगड़िया के पास से खनिज गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त 01 वाहन फॉर्माटेक ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 48 जेडबी 9194 को जप्त कर पुलिस थाना कोतवाली बैतूल की अभिरक्षा में खड़ा करवाया गया है। उपरोक्त अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रकरणों को न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनगणना 2027: फील्ड में जनगणना कार्यों की गुणवत्ता का किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में समस्त 21 चार्जो में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के अंतर्गत फील्ड कार्य उत्साहपूर्वक एवं सक्रियता के साथ किया जा रहा है। चार्ज अधिकारियों के मार्गदर्शन में प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा मकान सूचीकरण ब्लॉक की सीमाओं की स्थल पर पहचान की जा रही है। इसके साथ ही प्रगणकों द्वारा भवनों की पहचान एवं नंबरिंग करते हुए ड्राफ्ट ले-आउट मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा एचएलओ मोबाइल एप के सही संस्करण को डाउनलोड कर लॉग-इन करने के पश्चात हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एप पर प्रारंभिक प्रविष्टियां दर्ज की जा रही है। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे द्वारा जनगणना 2027 में कार्यों की गुणवत्ता डाटा की शुद्धता को सर्वोपरि रखा गया है। अपने सतत पर्यवेक्षण में उनके द्वारा जिला जनगणना अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों को गुणवत्ता जांच के लिए स्वयं फील्ड में जाकर कार्यों को देखने और समझने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल समाधान करने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में जनगणना कार्य के द्वितीय दिवस अतिरिक्त जनगणना अधिकारी श्री नरेंद्र गौतम और निदेशालय से आए जिला प्रभारी श्री भरत गौर तथा जिला जनगणना कार्यालय के तकनीकी प्रभारी श्री आशीष वागद्रे आदि द्वारा नगरीय चार्ज बैतूल के अंतर्गत विनोबा वार्ड में जाकर फील्ड कार्य का निरीक्षण किया।

बर्राढाना आगजनी पीड़ितों को त्वरित आर्थिक सहायता

संकट की घड़ी मध्यप्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ, हर संभव मदद दी जाएगी : विधायक हेमंत

बैतूल (निप्र)। भीमपुर ब्लॉक के ग्राम बर्राढाना में हुई भीषण आगजनी के बाद पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है। रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और उन्हें हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने आगजनी से प्रभावित सभी परिवारों को व्यक्तिगत रूप से तात्कालिक आर्थिक 10 -10 हजार रुपए की नगद सहायता राशि प्रदान की, जिससे पीड़ितों को तुरंत राहत मिल सके। विधायक श्री खंडेलवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी चर्चा की है, जिसमें संवेदनशील मुख्यमंत्री जी द्वारा आगजनी पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि बैतूल और भैंसदेही दोनों विधायकों की स्वेच्छानुदान निधि से प्रत्येक प्रभावित परिवार को 20-20 हजार रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। साथ ही आरबीसी 6-4 के प्रावधान के तहत भी पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नुकसान का विस्तृत आंकलन कर शीघ्र आर्थिक सहायता वितरित की जाए तथा पुनर्वास की व्यवस्था

सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद श्री मोहन नागर, विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य श्री सुधाकर पवार, कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

आगजनी से हुआ भारी नुकसान

शनिवार शाम ग्राम पंचायत बाशिंदा के बर्राढाना में अचानक लगी आग तेज हवाओं के कारण विकराल हो गई, जिससे मकान, घरेलू सामान और अनाज जलकर नष्ट हो गया। इस घटना में करीब 24 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 18 परिवारों को भारी और 6 को आंशिक नुकसान हुआ है।

संवेदनशीलता के साथ राहत कार्य जारी

शासन प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के लिए राशन इत्यादि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित परिवारों का स्वास्थ्य परिक्षण भी कराया गया है। साथ ही सामाजिक संस्थाएं भी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने मौके पर चले रहे राहत कार्यों का अवलोकन भी किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान श्री खंडेलवाल ने भरोसा दिलाया कि आर्थिक सहायता और पुनर्वास की हर संभव व्यवस्था प्राथमिकता के साथ की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवार जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें।

---

10 लाख रूपए तक के लंबित प्रकरणों के होंगे समझौते

हरदा (निप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 09 मई 2026 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी/अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जाएगा।

कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत विद्युत चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरणों एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण के लिये निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपील की है कि उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने विवादों को समाप्त करें और कानूनी कार्रवाई से बचें। कंपनी ने बताया है कि नेशनल लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्व राशि रू. 10,00,000 (दस लाख) तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र ''नेशनल लोक अदालत'' 09 मई 2026 को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी।

अधिकारियों ने किया उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले के सभी उपार्जन केंद्रों पर उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों द्वारा उपार्जन केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों ने श्यामपुर स्थित पवनपुंज वेयर हाउस, चरनाल स्थित मारुतिनंदन वेयरहाउस, महोड़िया स्थित ओम वेयरहाउस, कान्याखेड़ी स्थित पटेल वेयरहाउस, खजूरिया कला स्थित सीताराम वेयरहाउस, मानपुरा स्थित श्री कृष्णा वेयरहाउस, संग्रामपुर वेयरहाउस, पीलूखेड़ी स्थित गायत्री वेयरहाउस और टकीपुर स्थित वेयरहाउस सहित अनेक उपार्जन केंद्रो का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने केंद्रों पर किसानों के लिए उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं जैसे पेयजल, शेड एवं अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की और

निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही केन्द्रों पर प्रतीक्षारत किसानों की तौल प्रक्रिया को तेज करने के लिए उपार्जन संस्थाओं को टोकन जारी करने तथा तौल कांटों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

जिले की सभी आंगनबाड़ियों में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम आयोजित

सीहोर (निप्र)। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जिले की सभी आंगन ?ब ?ाड़ियों में लाड़ली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर के गंज स्थित शासकीय स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लाड़ली लक्ष्मी बालिका प्रियांशी चौहान ने इस योजना के लाभ के बारे में सभी को जानकारी दी।

कलेक्टर ने लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की

सीएम हेल्पलाइन तहत दर्ज शिकायतों का शीघ्रता से निराकरण के निर्देश

क्षीरधारा योजना, हरित क्रांति भूमि की नीलामी, गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य कार्यों के संबंध में दिशा-निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज समय सीमा बैठक में लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की है। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभा कक्ष में उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों सहित विकासखंड स्तर से ऑनलाइन जुड़े अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन तहत दर्ज शिकायतों के निराकरण कार्यों में तेजी लाएं, उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व संबंधी सीएम हेल्पलाइन तहत दर्ज शिकायतों का निराकरण कर ए ग्रेड में शामिल होने का प्रयास करें। इसके अलावा उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे राहत राशि, पीएम किसान सम्मान निधि, पेंशन सहित इत्यादि योजनाओं में फेल हुए ट्रांजेक्शन मामलों में गंभीरता दिखाते हुए त्रुटि सुधार कर हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है की योजनाओं में सिंगल क्लिक से भुगतान हुआ है जो भी भुगतान असफल हुए हैं उनकी जानकारी एकत्रित कर त्रुटि सुधाकर पात्र हितकारी को लाभान्वित कराएं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर संबंधित क्षेत्र के

एसडीएम को भी इन कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा है ट्रांजैक्शन फेल में दर्ज गलत जानकारी या जो भी टेक्निकल समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में निजी या शासकीय भूमि पर कब्जे, नामांतरण इत्यादि की लंबित शिकायतों की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन शिकायतों का शीघ्र निराकरण कराएं। साथ ही आगामी टीएल बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को 500 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों की जानकारी लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी बताएंगे कि 500 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का निराकरण क्यों नहीं हुआ यह शिकायतें क्यों लंबित रही हैं। बैठक में उन्होंने जिले में संचालित गौशालाओं में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील हैं या नहीं के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। बैठक में क्षीरधारा योजना के प्रथम चरण तहत क्रियान्वित कार्यों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान बताया गया कि इस योजना तहत 53 ग्राम चयनित चयनित किए गए हैं जिनमें बेस लाइन सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बैठक में हरित क्रांति भूमि की नीलामी सभी तहसीलों के अधिकारियों से संवाद कर प्राप्त की गई है, शेष नीलाम रही भूमियों की नीलामी नियमानुसार करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को प्रदाय होने वाली साइकिलें कबाड़ तो नहीं हो रही की रिपोर्ट दें - कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित सभी स्कूलों में यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्कूल में शासन की योजना तहत प्रदाय होने वाली पुरानी साइकिलें कबाड़ तो नहीं हो रही हैं। यदि पुरानी साइकिले हैं तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि वे ध्यान दें कि जो भी बच्चा जिस स्कूल या आंगनबाड़ी में दर्ज है उसका समग्र वहीं का हो बच्चों को ग्राम या नगरीय क्षेत्र में शिफ्ट करते हैं तो उसका समग्र स्थानीय स्तर पर ही हो यह सुनिश्चित करें, ताकि बच्चे को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में कोई परेशानी ना आए। दोनों विभागों पर इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की प्रवेश संख्या बढ़ाने पर जोर - कलेक्टर श्री गुप्ता ने शासकीय स्कूलों में बच्चों की प्रवेश संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है।

बढ़ते तापमान के दृष्टिगत लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बढ़ते हुए तापमान से स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रवभावों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सीएमएचओ डॉ सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि इस संबंध में जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों को सतत निगरानी एवं उपचार के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों का उन्मुखीकरण भी किया जा रहा हैं। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के अधिकारियों को आने वाले मरीजो की लू के लक्षणों की जांच करने, उचित प्रबंधन करने, ठंडे पेयजल की व्यवस्था करने तथा वार्ड में शीतलता के लिए पंखों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि तेज धूप एवं ज्यादा देर तक रहना लू लगने का प्रमुख कारण होता है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे इलेक्ट्रोराइड का असंतुलन हो जाता हैं। उन्होंने बताया की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में एक हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट बनाई जा रही हैं एवं गर्मी से संबंधित बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक दवाइयां संस्थाओं में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ओआरएस कार्नर बनाए जा रहे हैं। संवेदनशील समूहों जैसे गर्भवती महिला, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए भी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाओं के निर्देश जारी किये गए है।

क्या न करें

सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि गर्मी के दौरान लू से बचाव के लिए दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच धूप में न निकलें, इस समय लू लगने की संभावना अधिक होती है। मदिरा, चाय, कॉफी इत्यादि का अत्याधिक सेवन न करें। कोई भी अधिक मेहनत का कार्य करते समय पर्याप्त पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचें। बासे भोजन का सेवन न करें। भीड़भाड़ वाली जगाहों पर जाने बचें। इसके साथ ही लू के लक्षण दिखाई देने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें।

माचना नदी से जलकुंभी हटाने को फिर जुटे श्रमदानियों के हाथ

बैतूल (निप्र)। जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 के अंतर्गत जिले की जीवनदायिनी मां माचना नदी को जल खरपतवार जलकुंभी से मुक्त करने के उद्देश्य से नियमित श्रमदान के तहत रविवार को पुनः विशेष श्रमदान अभियान आयोजित किया गया। यह अभियान पद्मश्री मोहन नागर उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद व राज्य मंत्री दर्जा के नेतृत्व में सदर क्षेत्र स्थित घाट पर प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक संचालित हुआ। लगातार दूसरे रविवार को चले इस अभियान में लगभग 55 श्रमदानियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नदी से जलकुंभी निकालने का कार्य किया।

इस अवसर पर पद्मश्री श्री मोहन नागर द्वारा जल संवाद करते हुए सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि मां माचना बैतूल की जीवनदायिनी व तवा में मिलकर यह मां नर्मदा की सहायक नदी है, इसकी रक्षा करना हम सबका कर्त्तव्य है। मानव संकल्प और मानव श्रम से कोई भी कार्य सम्भव हो जाता है। उन्होंने आगामी रविवार को भी अधिकाधिक संख्या में श्रमदान के लिए

उपस्थित होने का आह्वान किया।

जिला समन्वयक श्रीमती प्रिया चौधरी ने बताया कि यह अभियान प्रति रविवार को प्रातः 7 बजे से 8.30बजे तक चलेगा। साथ ही मानव श्रमदान के साथ ही नगरपालिका प्रशासन द्वारा मशीनों से भी जलकुम्भी निकाली जाएग। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे मां माचना को स्वच्छ एवं संरक्षित बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाएं अभियान में ग्रीन टाइगर संस्था के पर्यावरण प्रेमी तरुण वैद्य अपनी टीम सहित उपस्थित रहे। साथ ही पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं माचना जन्मोत्सव समिति के संयोजक श्री आनंद प्रजापति, स्थानीय पार्षद, ग्यारह दोहे रामायण की टीम, जन अभियान परिषद बैतूल से संबंधित नवांकुर संस्थाएं अंश सेवा समिति, भूपेंद्र महिला एवं बाल कल्याण समिति, प्रदीपन संस्थाके सदस्य, सीएमसीएलडीपी के छात्र, परामर्शदाता आशीष कोकने, राजू आठनेरे, प्रमोद जागरे तथा समाजसेवी दिनेश सोनी सहित वार्डवासियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के कलेक्टरों को मिल सकेंगे अधिकार

भोपाल की आदमपुर कचरा खंती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मोबाइल कोर्ट चलाने का भी प्लान

भोपाल (नप्र)। भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में आग लगने के केस में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के कलेक्टरों को अधिकार दिए जाने पर बात की गई। वहीं, मोबाइल कोर्ट चलाने का भी प्लान बनाने को कहा गया। इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 भोपाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू हो।

यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से जुड़ा है। पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी. पांडे ने आदमपुर खंती में आग लगने की घटनाओं को लेकर एनजीटी में मार्च 2023 में याचिका दाखिल की थी। इस पर 31 जुलाई-23 को नगर निगम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ निगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर 16 मई-25 को सुनवाई हुई थी। इसमें निगम की ओर से जुर्माने की राशि माफ किए जाने की मांग रखी गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में एमपी के मुख्य सचिव समेत 6 वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रतिवादी बनाया जा चुका है। 19 फरवरी को फिर से सुनवाई हुई थी।

सुनवाई में देशभर के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया– केस दाखिल करने वाले पर्यावरणविद् डॉ. सुभाष सी. पांडे ने बताया कि सुबह मामले में सुनवाई की गई। इसमें कहा गया कि ये केस भोपाल या इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या है। इसलिए इस सुनवाई में देश के विभिन्न मुख्य सचिवों को बुलाया गया था।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था

पर्यावरणविद् डॉ. पांडे ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि 1 अप्रैल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू हो जाएंगे। नए नियम देश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या की पहचान करने और उसे हल करने के तरीके में पूरी तरह से शामिल हैं। इस नियम के मकसद को पूरा करने के लिए ऐसे निर्देश जारी करना सही समझते हैं, जो न सिर्फ भोपाल नगर निगम पर बल्कि पूरे देश पर लागू हों। इसका कारण यह है कि लोकल बॉडीज द्वारा एसडब्ल्यूएम रूल्स, 2016 के हिसाब से पालन की स्थिति कुछ हद तक या तो पालन कर रही हैं या नहीं। नियम के तहत आने वाली चुनौतियों को उस तरह से हल नहीं किया जा सकता, जैसे उन्हें पुरानी व्यवस्था में उन अधिकारियों द्वारा हल किया जाता था। जिन्हें संसद का अधिकार क्षेत्र है।

कोर्ट ने साफ कहा है कि नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से लागू नहीं हो सकेगा। कुछ सीएस ने अपनी समस्याएं भी बताईं। कर्नाटक, मप्र, बिहार समेत अन्य मुख्य सचिवों से बात भी की। उन्होंने कहा कि नया प्लान बना रहे हैं।

डॉ. पांडे ने बताया, कोर्ट ने कहा कि 1 साल के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 की धारा 5 का अधिकार कलेक्टर को दे रहे हैं। यानी, सभी अधिकारों को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और निगम से लेकर कलेक्टरों को पॉवर देंगे। सभी चीफ सेक्रेटरी ने भी हामी भरी है। अगली सुनवाई 22 मई को होगी। जिसमें सुप्रीम के आज के आदेश जैसे कलेक्टर को पॉवर देना, कचरा छंटनी, पैनाल्टी आदि के बारे में बताएंगे। मोबाइल कोर्ट भी चलाएंगे। ताकि, मौके पर जुर्माना किया जा सके।

सलाना रिपोर्ट में स्थिति ठीक नहीं– कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेस्ट मैनेजमेंट पर सालाना रिपोर्ट 2021-2022 बताती है कि देश में घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सहायक कामों से हर दिन करीब 1.70 लाख टन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैदा होता है। हम देखते हैं कि भले ही भोपाल और इंदौर जैसे कई शहरों में कलेक्शन एफिशिएंसी में सुधार हुआ है, लेकिन प्रोसेसिंग की दर अभी भी एक बड़ी रुकावट बनी हुई है।

भोपाल के केस के बारे में ये कहा

पिछली सुनवाई के आखिरी में भोपाल निगम से जुड़े केस को लेकर कहा था कि आदमपुर छावनी डंप साइट के मामले में पुराने कचरे के लिए कुछ और पेपरवर्क पूरा करने की जरूरत है। टेंडर को फाइनल करने में कुछ और समय लगेगा। इसलिए वह इस मामले में टेंडर को फाइनल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगती हैं। उन्हें यह समय दिया जाता है।

भोपाल में रोज निकलता है साढ़े 8 सौ टन कचरा

जानकारी के अनुसार, भोपाल से हर रोज 850 टन कचरा निकलता है। प्रोसेसिंग के लिए 800 टन खंती पहुंचता है। इसमें से 290 टन कचरा मिट्टी होती है। बाकी बचा 510 टन मिक्स कचरा होता है। निगम के पास जो यूनिट है, वह 420 टन की ही क्षमता है।

तीन दिन पहले भी लग चुकी है आग

तीन दिन पहले भी आदमपुर खंती में आग लग चुकी है। खास बात यह है कि खंती में डंप लिगेसी वेस्ट के निपटारे का काम शुरू करने के लिए एक दिन पहले ही पूजा की गई थी। इसके बाद कचरे में आग लग गई। आग लिगेसी वेस्ट के साथ नए ड्राय वेस्ट में भी लगी थी। इस नए ड्राय वेस्ट का उपयोग एनटीपीसी के प्लांट में टोरिफाइड चारकोल बनाने में होना था। आग के कारण एक बार फिर इलाके में धुआं फैल गया और ग्रामीण दिन भर परेशान होते रहे।

साइट पर 6.5 से 7.5 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट जमा

खंती में डंप लिगेसी वेस्ट के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद निगम ने 26 मार्च को सौराष्ट्र एन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड को वर्क ऑर्डर जारी किया। साइट पर 6.5 से 7.5 लाख मीट्रिक टन लिगेसी वेस्ट जमा है। कंपनी को इसके लिए 55 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।

बरगी डैम हादसे वाले क्रूज को काटने पर बवाल

मंत्री बोले-'निकालते वक्त टूटा', पुलिस का दावा-'शव ढूंढने को काटा'

जबलपुर (नप्र)। बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस हादसे में कम से कम 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अब खबर आ रही है कि जिस जहाज में हादसा हुआ था, उसे जांच पूरी होने से पहले ही आनन-फानन में काट दिया गया है। इस जल्दबाजी ने प्रशासन की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पीड़ितों का फूटा गुस्सा– हादसे में बाल-बाल बचे एडवोकेट रोशन आनंद का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उन्होंने बताया कि जब अभी जांच चल ही रही है, तो जहाज को नष्ट क्यों किया गया? रोशन ने कहा, यह सब इसलिए किया गया ताकि असलियत कभी सामने न आ सके। अब कोई सुबूत नहीं बचा, तो सच्चाई कैसे पता चलेगी?

बयानों में भारी झोल– हैरानी की बात यह है कि जहाज को नष्ट करने के पीछे सरकार और पुलिस के बयानों में जमीन-आसमान का फर्क है।

पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा इसे जानबूझकर नहीं काटा गया, बल्कि पानी से बाहर निकालते समय जहाज खुद-ब-खुद टूट गया।

सीएसपी अंजुल आयंक मिश्रा-जहाज को इसलिए काटा गया ताकि यह चेक किया जा सके कि कहीं अंदर कोई शव तो नहीं फंसा है। इसे एसडीआरएफ ने डिस्मेंटल किया।

बिना इंश्योरेंस और खराब इंजन के चल रहा था क्रूज?

सूत्रों की मानें तो यह जहाज बिना इंश्योरेंस के चल रहा था और इसके दो इंजनों में से एक पहले से ही खराब था। जब इस बारे में एमपी टूरिज्म के जीएम (ऑपरेशंस) अजय श्रीवास्तव से पूछा गया, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं इस पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, और मुझे इंजन की खराबी की कोई शिकायत नहीं मिली थी।

खंडवा में खनन माफिया का दुस्साहस

पटवारी को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश, केस दर्ज

खंडवा (नप्र)। अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खंडवा तहसील के जावर सर्किल अंतर्गत ग्राम भकराडा में मुरम के अवैध उत्खनन की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और पटवारी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश का मामला भी सामने आया है।

मौके से आरोपी फरार– जानकारी के अनुसार हल्का पटवारी मयंक फुलेरिया जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मुरम का उत्खनन किया जा रहा था। मौके पर एक जेसीबी मशीन और चार ट्रैक्टर मौजूद थे, जिनके जरिए मुरम को पास के मुर्गी केंद्र तक ले जाया जा रहा था। पटवारी को देखकर मौके पर मौजूद लोग भागने लगे। इस दौरान ट्रैक्टर चालक कुंदन पिता गजेंद्र राजपूत ने पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि पटवारी ने सतर्कता दिखाते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई।

जेसीबी जब्त, अन्य वाहन मौके से भागे– घटना के बाद सभी ट्रैक्टर चालक अपने वाहन लेकर फरार हो गए, लेकिन जेसीबी मशीन गड्ढे में फंसने के कारण मौके से नहीं निकल सकी। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेसीबी को जब्त कर थाना जावर की अभिरक्षा में सौंप दिया है। प्रारंभिक जांच में जेसीबी चालक की पहचान सावन भिलाला निवासी बांगरदा और एक अन्य ट्रैक्टर चालक की पहचान मुकेश सोलंकी निवासी बिजोरा भील के रूप में हुई है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221, 132, 110, 303(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 21 और 4 के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। महेश सोलंकी, तहसीलदार, खंडवा

खंडवा डीआईजी मनोज कुमार राय ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्य में बाधा डालना और जान से मारने की कोशिश जैसे गंभीर अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अवैध उत्खनन में लिप्त माफियाओं के हौसले पस्त किए जा सकें।

क्रूज हादसे में घायलों से निजी अस्पतालों ने वसूले रुपए

नोबल अस्पताल पर कार्रवाई-जबलपुर हास्पिटल को छोड़ा, लाइसेंस किया निरस्त, सात दिन में मांगा स्पष्टीकरण

जबलपुर (नप्र)। बरगी बांध क्रूज हादसे में घायल हुए नेपाल के एक परिवार से इलाज के बाद पैसे वसूलने वाले नोबल अस्पताल का लाइसेंस प्रशासन ने एक माह के लिए निरस्त कर दिया है, जबकि दूसरे जबलपुर अस्पताल पर कार्रवाई नहीं हुई है। गुरुवार को हुई घटना के बाद जैसे-तैसे घायल गौर तिराहा स्थित नोबल मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल और जबलपुर हास्पिटल पहुंचे, जहां घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया और फिर पीड़ितों को बिल थमा दिया। शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

संभागीय कमिश्नर ने सीएमएचओ को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। सोमवार की रात को स्वास्थ्य विभाग ने नोबल मल्टीस्पेशलिस्ट अस्पताल का लाइसेंस एक माह के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि इलाज के लिए साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएमएचओ ने अस्पताल संचालक को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान मरीजों का समुचित इलाज कर डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन

अगले एक महीने तक कोई नया मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपदा के समय किसी भी तरह की लापरवाही या वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में पाया गया कि दुर्घटना में घायल मरीजों से शुल्क लेना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के खिलाफ है। इस पर अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा गया है।

नेपाल करेंसी थी फिर भी नहीं मिली राहत

करूज हादसे में घायल नेपाल के परिवार ने बताया था कि वे किसी तरह जान बचाकर अस्पताल पहुंचे थे। वहां स्टाफ ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन तुरंत 4500 रुपए का बिल थमा दिया। पीड़ित बार-बार बताते रहे कि उनका पैसा पानी में भीग गया है और उनके पास भारतीय मुद्रा भी नहीं है, फिर भी अस्पताल प्रबंधन ने उनकी एक नहीं सुनी।

पीड़ित महिला सविता वर्मा ने अस्पताल से कहा कि उनके पास सिर्फ नेपाली करेंसी थी, मोबाइल भी खराब हो गया था। इसके बावजूद अस्पताल स्टाफ ने भुगतान पर ही जोर दिया। आखिरकार बनारस में रहने वाले रिश्तेदार से संपर्क कर 4500 रुपए जमा करवाने के बाद ही उन्हें राहत मिली। सविता ने मीडिया को बताया कि अस्पताल वालों ने पहले 2200, फिर 3000 और अंत में 4500 रुपए की मांग की गई। अस्पताल प्रबंधन का साफ कहना था कि पूरा पैसा दिए बिना मरीज को नहीं छोड़ा जाएगा। इससे परिवार में डर का माहौल बन गया।

कई जिलों में बारिश, डिंडौरी में ओले गिरे

39 जिलों में भी अलर्ट, मौसम वैज्ञानिक बोले- 8 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में मंगलवार सुबह से धार, बड़वानी, झाबुआ सहित कई जिलों में बारिश हुई, वहीं दोपहर में डिंडौरी में ओले गिरे।

भोपाल मौसम केंद्र ने प्रदेश के 39 जिलों में 40 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया और कटनी में आंधी की रफ्तार सबसे ज्यादा रहेगी। वहीं, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, रीवा, सतना, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में बारिश होने की संभावना है।सोमवार को भी 15 से ज्यादा जिलों में आंधी-पानी का दौर जारी रहा। कहीं-कहीं ओले भी गिरे थे।

प्रदेश में एक साइक्लोनिक सकुर्लेशन (चक्रवात)

एक्टिव है। वहीं, पास से दो ट्रफ भी गुजर रही हैं। इस वजह से कहीं ओले गिर रहे हैं तो तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। 8 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा।

डिंडौरी में आधा घंटे तेज बारिश, कई जगह टीन शेड उड़े– डिंडौरी जिले के मेहदवानी जनपद मुख्यालय में दोपहर में तेज आंधी तूफान आया। इससे एक पेड़ उखड़कर आजीविका दीदी कैफे के छप्पर पर गिर गया। इसमें किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन टीन शेड उखड़ गया।

मुंबई-आगरा हाईवे पर चलती बस से अचानक निकलने लगा धुआं

ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ तो बची यात्रियों की जान

बड़वानी (नप्र)। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया, जब आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागलवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक यात्री बस के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और देखते ही देखते बस के भीतर घना धुआं भर गया। बालसमुद्र पुलिस चौकी प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि घटना साली कला गांव के पास हुई, जब सेंधवा से बड़वानी जा रही बर्मन ट्रेवल्स की बस में यह स्थिति बनी।

बस से अचानक उठने लगा धुआं– बस से अचानक धुआं उठते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। कई यात्री घबराकर तुरंत नीचे उतरने लगे, जबकि कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए बस से कूदना ही बेहतर समझा। चालक रविंद्र गवले ने तत्परता दिखाते हुए बस को तुरंत सड़क किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलने के निर्देश दिए। बस में करीब 20 यात्री सवार थे जो समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

टर्बोचार्जर में आई थी खराबी

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बस के टर्बोचार्जर में खराबी आ गई थी। चालक के अनुसार इंजन ऑयल लीक होकर इनटेक सिस्टम में पहुंच गया और ईंधन की तरह जलने लगा, जिससे इंजन की गति अनियंत्रित हो गई और भारी धुआं निकलने लगा। बस का इग्निशन स्विच भी काम नहीं कर रहा था, जिससे इंजन बंद करना मुश्किल हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लोगों में दहशत और नाराजगी दोनों देखी गई। यह घटना बड़वानी जिले में संचालित यात्री बसों की जर्जर स्थिति और नियमों की अनदेखी को उजागर करती है। बसों में अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स तथा किराया सूची जैसे अनिवार्य संसाधनों का अभाव है। कई बसों के इमरजेंसी गेट रस्सियों और तारों से बांधकर रखे गए हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में गंभीर खतरा बन सकते हैं।

अन्य जिलों में पंजीकृत बसें हो रही हैं संचालित

जानकारी के अनुसार, अन्य जिलों में पंजीकृत करीब 200 बसें बड़वानी में संचालित हो रही हैं। इस मामले में आरटीओ राकेश भूरिया ने कहा कि समय-समय पर जांच की जाती है और जल्द ही विशेष अभियान चलाकर लापरवाह बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

3 लोगों के ऊपर से बोरिंग मशीन रिवर्स कर निकाली, मौत

धार के पीथमपुर में काम के बाद गाड़ी के नीचे सो रहे थे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे

धार (पीथमपुर) (नप्र)। धार जिले के पीथमपुर सेक्टर एक में बोरिंग मशीन गाड़ी की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। हादसा मंगलवार तड़के 4 बजे गवला गांव में हुआ। दरअसल, छत्तीसगढ़ निवासी तीनों मजदूर गाड़ी के नीचे सो रहे थे। ड्राइवर ने ट्रक को रिवर्स किया, तभी पिछला टायर मजदूरों पर चढ़ गया।

खेत पर बोरिंग का काम चल रहा था

पुलिस के अनुसार, गवला निवासी सुभाष चौहान और रुदन सिंह सोलंकी के खेत पर बोरवेल का काम चल रहा था। काम के बाद थके हुए मजदूर बोरिंग मशीन वाहन के साथ चलने वाली सपोर्टिंग एयर गाड़ी (KA 51 MC 5799) के नीचे आराम करने के लिए लेट गए, तभी ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक ट्रक को रिवर्स कर दिया। उसे नीचे सो रहे मजदूरों का आभास

नहीं हुआ और ट्रक का पिछला टायर सीधे उनके ऊपर चढ़ गया।

हादसे में रामचरण पिता मेघनाद (56) निवासी खरधाढ़ी (छत्तीसगढ़), भानुप्रताप (19) पिता त्रिभुवन साय निवासी सोनगेरसा (छत्तीसगढ़) और अरविंद (22) पिता नमूलराम करमापारा, (छत्तीसगढ़) की मौके पर ही मौत हो गई।

ड्राइवर पर केस दर्ज, शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा– फरियादी रमेश इक्का की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, यह घटना ड्राइवर की लापरवाही कारण हुई, क्योंकि बिना किसी सावधानी या जांच के अंधेरे में भारी वाहन को पीछे लिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर वाहन को जब्त कर लिया है।

नरसिंहपुर में इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत – नरसिंहपुर में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे इथेनॉल प्लांट में डीडीएस टैंक अचानक गिर गया। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला बचई स्थित महाकौशल शुगर मिल परिसर में हुई।